



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 6, 1993/कार्तिक 15, 1915

No. 45]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 6, 1993/KARTIKA 15 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than
Ministry of the Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(विधि कार्य विभाग)

(Department of Legal Affairs)

न्यायिक खण्ड

Judicial Section

सूचना

NOTICE

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1993

New Delhi, the 7th October, 1993

का.आ. 2310.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री ओम प्रकाश, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे करनाल (हरियाणा) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आशेन इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजी जाए।

S.O. 2310.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Om Prakash, Advocate for appointment as a Notary to practise in Karnal (Haryana).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[सं. 5(101)/93-न्यायिक]

[No. F. 5(101)/93-Judl.]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर 1993

का.आ. 2311.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री मयंकरे गुलाब शंकर शुक्ला, एडवोकेट को उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए किया है कि उसे महाराष्ट्र राज्य में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(105)/93-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 15th October, 1993

S.O. 2311.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Mayankar G. Shukla, Advocate for appointment as a Notary to Practise in Maharashtra State.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(105)/93-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 1993

का.आ. 2312.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री विनय एस. मसूरकर, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे बम्बई (महाराष्ट्र में) व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(104)/93-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 15th October, 1993

S.O. 2312.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Vinay S. Masurkar, Advocate for appointment as a Notary to practise in Bombay (Maharashtra).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(104)/93-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 1993

का.आ. 2313.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री मदन लाल दूबे, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए किया है कि उसे झालावाड़ (राजस्थान) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(102)/93-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 15th October, 1993

S.O. 2313.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Madan Lal Dubey, Advocate for appointment as a Notary to practise in Jhalawar (Rajasthan).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(102)/93-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 1993

का.आ. 2314.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री ईब्राहिम आई. वोहरा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे बड़ौदा (गुजरात राज्य) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(103)/93-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 15th October, 1993

S.O. 2314.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Ibrahim I. Vohra, Advo-

cate for appointment as a Notary to practise in Baroda (Gujarat).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(103)/93-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

ment, allegedly committed by Shri Jagannath Sharma, Managing Director, Bramhaputra valley Handloom Cooperative Weavers Society Limited and others. And for investigation of attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other offence/offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228/7/93-AVD.II]

PARAG PRAKASH, Dy. Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 1993

का. आ. 2315.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम सरकार राजनैतिक विभाग अधिसूचना सं. पो. एल. ए./बा/77/92/58 तारीख 1-6-1993 द्वारा संसूचित राज्य सरकार की सहमति से केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई साहायिकी के मामले में श्री जगन्नाथ शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, बहापुत्र घाटी हथकरवा सहकारी बुनकर सोसाइटी लिमिटेड और अन्य द्वारा किए गए अभिकथित कपट को बाबत भारतीय दंड संहिता की धारा 20-ख, 420, 408, 409 और अष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) (ग) और (घ) के साथ पठित धारा 13(2) के तत्स्थाना अष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1) (ग) और (घ) के साथ पठित धारा 5(2) के अधिनियम अपराधों के अन्वेषण के लिए और उक्त अपराधों और उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न उसी संभवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध/अपराधों के संबंध में या उससे संबंधित प्रयासों, बुध्दियों और षड्यंत्रों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण असम राज्य पर करता है।

[संख्या—228/7/93-ए.वो.डो.-II]

पराग प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 19th October, 1993

NOTIFICATION

S.O. 2315. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government, with the consent of the State Govt. communicated vide Government of Assam Political (A) Deptt. Notification No. PLA/V/77/92/58 dated 1-6-1993 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Assam for investigations of offences punishable under Sections 120B, 420, 408, 409 Indian Penal Code and Section 5(2) read with 5(1)(c) and (d) of Prevention of Corruption Act, 1947 corresponding to Section 13(2) read with 13(1)(c) and (d) of the Prevention of Corruption Act, 1988 in respect of fraud in the matter of subsidy sanctioned by the Central Govern-

नई दिल्ली 19 अक्टूबर, 1993

का. आ. 2316.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से जो गृह (एम. सो.—ए) विभाग जो. ओ. आर. डो. सं. 1883 तारीख 8 जुलाई, 1993 द्वारा वो गई थी, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रजिस्ट्रिकृत एस. आई. आर. 36/91—हैदराबाद तारीख 22-7-1991 में नीचे उपर्युक्त सुसंगत अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय अपराधों और उक्त अपराधों तथा वैसे ही या उन्हीं या उनसे संबंधित तथ्यों से उद्भूत होने वाले संभवहार के अनुक्रम के लिए किए गए किसी अन्य अपराधों के संबंध में या उनसे संसक्त प्रयत्नों, बुध्दियों और षड्यंत्र के अन्वेषण के लिए जो निम्नलिखित प्रादेशिक व्यक्तियों द्वारा किए गए अभिकथित हैं, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य पर करता है;

नाम	विधि की धारा
1. श्रीमती एम. योजना, मैसर्स वेस्ट साजिकल इंडस्ट्रोज निवासी 55856 मिथिला नगर, कालोनी रोड, सं. 12, बंजारा हिल, हैदराबाद।	अष्टाचार निवारण अधि- नियम, की धारा 13 (1) (घ) के साथ पठित 13(2) भारतीय दंड संहिता की धारा 420 468, 471 के साथ पठित 120 ख और
2. मिस भवानी, मैसर्स वेस्ट साजिकल इंडस्ट्रोज निवासी 55856 मिथिला नगर, कालोनी रोड, सं. 12 बंजारा हिल, हैदराबाद।	अष्टाचार निवारण अधि- नियम की धारा 13 (1) (घ) के साथ पठित धारा 420, 468, 471 के अधीन मूल अपराध।
3. एम. डी. खुन्टे, मैसर्स लक्ष्मी इस्पात उद्योग, निवासी 251 चेनाय ट्रेड सेन्टर, पार्क लेन, सिकन्दराबाद।	अष्टाचार निवारण अधि- नियम की धारा 13 (1) (घ) के साथ पठित
4. के. राजेश, मैसर्स लक्ष्मी इस्पात उद्योग, निवासी 251 चेनाय ट्रेड सेन्टर, पार्क लेन, सिकन्दराबाद।	13(2) के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468, 471 के अधीन मूल अपराध।

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 1993

5. के. कालिदास,
मैसर्स इस्पात उद्योग,
निवासी 251 चेनाय ट्रेड सेंटर,
पार्क लेन, सिकन्दराबाद।

6. प्रभा खिस्ते,
मैसर्स लक्ष्मी इस्पात उद्योग,
निवासी 251 चेनाय ट्रेड सेंटर,
पार्क लेन, सिकन्दराबाद।

[सं. 228/73/93—ए. वी. डी.—II]

पराग प्रकाश, उप सचिव

New Delhi, the 19th October, 1993

S.O. 2316.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946) the Central Government, with the consent of the State Government of Andhra Pradesh accorded vide Home (SC-A) department G.O. Rt. No. 1883 dated 8-7-1993 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Andhra Pradesh for investigation of the offences in SIR 36/91-Hyd. dated 22-7-1991 registered by the Central Bureau of Investigation and attempts, abetments and conspiracy in relation or in connection with the said offences (and any other offences committed in the course of the same transaction and or arising out of the same or related facts, punishable under the provisions of relevant Act, indicated below alleged to have been committed by the following private persons,

Name	Section of Law
1	2
3	
1. Mrs. M. Yojna of M/s. Best Surgical Industries R/o 55856 Mithilanagar Colony Road No. 12 Banjara Hills, Hyderabad.	Under Section 120B read with 420, 468, 471, 13(2) read with 13(i)(d) of Prevention of Corruption Act and Substantive Offences Under Section 420, 468, 471, IPC read with 13(2) r/w 13(1)(d) of the P.C. Act.
2. Miss Bhawani of M/s. Best Surgical Industries R/o 55856 Mithilanagar Colony Road No. 12 Banjara Hills, Hyderabad.	
3. M.D. Khunte of M/s. Laxmi Ispat Udyog r/o 251 Chenoy Trade Centre, Park Lane Secunderabad.	
4. K. Rajesh of M/s. Laxmi Ispat Udyog r/o 251 Chenoy Trade Centre Park Lane, Secunderabad.	
5. K. Kalidas of M/s. Laxmi Ispat Udyog R/o 251 Chenoy Trade Centre, Park Lane, Secunderabad.	
6. Prabha Khiste of M/s. Laxmi Ispat Udyog R/o 251 Chenoy Trade Centre, Park Lane, Secunderabad.	

[No. 228/73/93- AVD-II]
PARAG PRAKASH, Dy. Secy.

का. आ. 2317.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से, जो गृह (एस. सी-ए) विभाग जी. ओ. आर. टी. सं. 1954, तारीख 19 जुलाई, 1993 द्वारा दी गई थी, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रजिस्ट्रीकृत एस. आई. आर. सं. 7/93—बी. एस. पी. तारीख 8 जून, 1993 में नीचे उपदर्शित मुसंगत अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय अपराधों और उक्त अपराधों तथा वैसे ही और/या उन्हीं या उनसे संबंधित तथ्यों से उद्भूत होने वाले संभवहार के अनुक्रम में किए गए किन्हीं अन्य अपराधों के संबंध में या उनसे संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षडयंत्र के अन्वेषण के लिए, जिनके बारे में यह अभिकथन है कि वे निम्नलिखित प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य पर करती है:

अभियुक्त का नाम विधि की धाराएं और एस. आई. आर. सं.

श्रीमती बी. लक्ष्मी कंतम्मा पत्नी जी. बेकु रेड्डो सं. 16/1938, श्रीनिवास अग्रहराम बल्लूर।	भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम सं. 45) की धारा 420 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 ख और छप्पाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन एस. आई. आर. सं. 7/93—बी. एस. पी., तारीख 08 जून, 1993.
---	---

[संख्या 228/71/93—ए. वी. डी.—II]

पराग प्रकाश, उप सचिव

New Delhi, the 19 October, 1993

S.O. 2317.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946) the Central Government, with the consent of the State Government of Andhra Pradesh Accorded vide Home (SC-A) Department G.O. Rt. No. 1954 dated 19-7-1993 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Andhra Pradesh for investigation of offences in SIR No. 7/93-VSP dated 8-6-1993 registered by the CBI and attempts

and conspiracy in relation to or in connection with the said offences and any other offences committed in the course of the same transaction and/or arising out of the same or related facts punishable under the provision of relevant act indicated below alleged to have been committed by the following private persons:—

Name of the Accused	Secs. of Laws & SIR No.
1	2
Smt. B. Lakshmi Kantamma w/o G. Venku Reddy No. 16/1938 Srinivasa Agraharam Vellore.	SIR No. 7/93-VSP dt. 8-6-93 Under Section 120B Indian Penal Code 1860 (Act No. 45 of 1860 read with 420 IPC and Sec. 13(2) read with 13(1)(d) of the P.C. Act, 1988.

[No. 228/71/93-AVD-II]

PARAG PRAKASH, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1993

का. आ. 2318.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 को उपधारा (1) द्वारा प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करने हुए, आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से, जो गृह (एल.सो.—ए) विभाग जी.ओ. आर. टा. सं. 1988, तारीख 24 जुलाई, 1993 द्वारा दो गई थी, नीचे उल्लिखित अपराधों और उक्त अपराधों तथा वैसे ही और/या उन्हीं या उनसे संबंधित तथ्यों से उद्भूत होने वाले संश्लेषण के अनुक्रम में किए गए किन्हीं अन्य अपराधों के संबंध में या उनसे संसक्त प्रयत्नों, घुसपैरियों और षड्यंत्र के अन्वेषण के लिए, जिनके बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो, हैदराबाद शाखा द्वारा रजिस्ट्रीकृत एस. आई. आर. सं. 27/92/एच. आई. डी. तारीख 1 सितम्बर, 1992 में यह अभिकथन है कि वे निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण आन्ध्र प्रदेश राज्य पर करती है :—

नाम	विधि की धाराएं
श्रीमती आर. रत्नाकुमारी, प्रबंध भागीदार, डा. आर. सत्यनारायणन्, मुख्य कार्यपालक मैसर्स अनुराधा एस्टेट्स, 3. 4. 874 इंडियन बैंक के सामने बरतकपुरा, हैदराबाद और अन्य	भारतीय बंड संहिता की धारा 420 के साथ पठित भारतीय बंड संहिता की धारा 120ब और अष्टाचार निवारण अधि- नियम, 1988 की धारा 13 (1)(घ) के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन।

[संख्या 228/72/93—ए. बी. डी.—II]

पराग प्रकाश, उप सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th October, 1993

S.O. 2318.—In exercise of the Powers conferred by sub-Section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment, Act, 1946 (Act No. 25 of the 1946) the Central Government, with the consent of the State Government of Andhra Pradesh vide Home (SC-A) Department GO Rt. No. 1988 dated 24-7-1993, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of State of Andhra Pradesh for investigation of the offences mentioned below:—

Name	Section of law.
1	2
Smt. R. Ratnakumari Managing Partner Dr. R. Satyanarayana, Chief Executive M/s. Anuradha Estates, 3.4.874 Opp. Indian Bank Barkatpura, Hyderabad and Ors.	Under Section 120-B IPC r/w 420 IPC r/w 13(2) r/w 13(i) (d) of the PC Act, 1988.

And attempts, abetments and conspiracy in relation to or in connection with the said offence (s) and any other offence(s) committed in the course of the same transaction and/or arising out of the same or related facts, punishable under the provisions of relevant Act, Alleged to have been committed by the aforesaid persons in S.I.R. No. 27/92/Hyd. dt. 1-9-92 and registered by the Central Bureau of Investigation, Hyderabad Branch.

[No. 228/72/93-AVD.-II]

PARAG PRAKASH, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1993

का. आ. 2319.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), नियमावली, 1976 के नियम-10 के उप नियम (4) के अनुसरण में (वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित) भारतीय साधारण बीमा निगम के निम्नलिखित कार्यालयों की, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :

कम्पनी का नाम :

नेशनल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

1. मण्डल कार्यालय—19, दिल्ली
2. मण्डल कार्यालय,—22, दिल्ली
3. मण्डल कार्यालय—24, दिल्ली
4. मण्डल कार्यालय—25, दिल्ली

5. शाखा कार्यालय—1, आसफ अली रोड
6. शाखा कार्यालय—2, आसफ अली रोड
7. शाखा कार्यालय, दरिया गंज
8. शाखा कार्यालय, झंडेवाला
9. शाखा कार्यालय, नेहरू प्लेस
10. शाखा कार्यालय—पंजाबी बाग
11. शाखा कार्यालय—रोशनारा रोड
12. शाखा कार्यालय—बसंत लोक (जमरूदपुर)
13. शाखा कार्यालय—डायरेक्ट एजेंट शाखा—2
14. शाखा कार्यालय रामगढ़, हजारी बाग
15. मण्डल कार्यालय—गया

[सं. 13011/1/92—हि.का.क.]

यशपाल गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 21st October, 1993

S.O. 2319.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following offices of the General Insurance Corporation of India Under the Administrative Control of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs) which or more than 80 per cent of staff have acquired working knowledge of Hindi.

Name of the Company : National Insurance Co. Ltd.,

1. Divisional Office-19, Delhi
2. Divisional Office-22, Delhi
3. Divisional Office-24, Delhi
4. Divisional Office-25, Delhi
5. Branch Office-1, Asaf Ali Road
6. Branch Office-2, Asaf Ali Road
7. Branch Office, Dariya Ganj
8. Branch Office-Jhandewalan
9. Branch Office, Nehru Place
10. Branch Office Punjabi Bagh
11. Branch Office, Roshnara Road
12. Branch Office, Basant Lok (Jamrودpur)
13. Branch Office-Direct Agent Branch-2
14. Branch Office, Ramgarh, Hazaribagh
15. Divisional Office, Gaya.

[No. 13011/1/92-HIC]

Y. P. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 1993

का. भा. 2320.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), नियमावली, 1976 के नियम—10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में (वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित भारतीय साधारण बीमा निगम के निम्नलिखित कार्यालयों को

जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :

कम्पनी का नाम

दि न्यू इंडिया इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

1. शाखा कार्यालय, हुडपसर
2. शाखा कार्यालय, नासिक शहर
3. शाखा कार्यालय, सातपुर
4. शाखा कार्यालय, अंबड
5. शाखा कार्यालय, शहर सांगली
6. शाखा कार्यालय मिरज
7. शाखा कार्यालय, इसलामपुर
8. शाखा कार्यालय, कोल्हापुर
9. शाखा कार्यालय, भूसावल
10. शाखा कार्यालय, अमरावती शहर
11. शाखा कार्यालय, वर्धा
12. शाखा कार्यालय, यवतमाल
13. मण्डल कार्यालय, कसारवाड़ी
14. शाखा कार्यालय चिचवड
15. शाखा कार्यालय, तलेगांव
16. शाखा कार्यालय, राजगुरु नगर
17. शाखा कार्यालय, सतारा शहर
18. शाखा कार्यालय, कहाड
19. शाखा कार्यालय, बारामती
20. शाखा कार्यालय, वाई
21. शाखा कार्यालय, अहमदनगर शहर
22. मण्डल कार्यालय, अहमदनगर
23. शाखा कार्यालय, श्रीरामपुर
24. शाखा कार्यालय, संगमनेर
25. शाखा कार्यालय, राठुरी
26. मण्डल कार्यालय—7, धुले
27. शाखा कार्यालय, धुले शहर
28. शाखा कार्यालय, मालेगांव
29. शाखा कार्यालय, अकोला शहर
30. मण्डल कार्यालय, अकोला
31. शाखा कार्यालय, नंदूरबार
32. शाखा कार्यालय, मलकापुर
33. शाखा कार्यालय, जलाना
34. मण्डल कार्यालय, रत्नागिरि
35. शाखा कार्यालय, रत्नागिरि शहर
36. शाखा कार्यालय, क्षिपलून
37. शाखा कार्यालय, कुडाल
38. मण्डल कार्यालय, इचलकरंजी शहर
39. शाखा कार्यालय, इचलकरंजी शहर
40. शाखा कार्यालय, जयसिंगपुर
41. शाखा कार्यालय, वारणानगर

42. शाखा कार्यालय, गड़हिलज
43. शाखा कार्यालय, नादेड़ नगर
44. शाखा कार्यालय, परभणी
45. शाखा कार्यालय, लातूर
46. मण्डल कार्यालय, पुणे
47. शाखा कार्यालय, विटा
48. प्रादेशिक कार्यालय-11 बं
49. शाखा कार्यालय, महाड़
50. शाखा कार्यालय, अलीबाग
51. शाखा कार्यालय, विले पार्ले
52. मण्डल कार्यालय, सोलापुर
53. शाखा कार्यालय, पठरपुर
54. शाखा कार्यालय, उस्मानाबाद

[सं. 13011/1/92-हि.का.क.]

यशपाल गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 21st October, 1993

S.O. 2320.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules 1976 the Central Government hereby notifies the following offices of the General Insurance Corporation of India (Under the Administrative Control of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs) where of more than 80 per cent of staff have acquired working knowledge of Hindi.

Name of the Company : The New India Assurance Co. Ltd.,

1. Branch Office, Hadpasar
2. Branch Office, Nasik City
3. Branch Office, Satpur
4. Branch Office, Ambad
5. Branch Office, Sangli City
6. Branch Office, Mirj
7. Branch Office, Islampur
8. Branch Office, Kolhapur
9. Branch Office, Bhusawal
10. Branch Office, Amrawati City
11. Branch Office, Vardha
12. Branch Office, Yawatmal
13. Branch Office, Kasarwadl
14. Branch Office, Chinchwad
15. Branch Office, Talagaon
16. Branch Office, Rajguru Nagar
17. Branch Office, Satara City
18. Branch Office, Kahad
19. Branch Office, Baramatl
20. Branch Office, Val
21. Branch Office, Ahmednagar
22. Branch Office, Ahmednagar
23. Branch Office, Shrirampur
24. Branch Office, Sigmner,
25. Branch Office, Bahuri
26. Divisional Office, Dhule
27. Branch Office, Dhule City
28. Branch Office, Malegaon
29. Branch Office, Nandurbar
30. Divisional Office, Akola
31. Branch Office, Akola City
32. Branch Office, Malkapur
33. Branch Office, Jalana
34. Branch Office, Ratnagiri

35. Branch Office, Ratnagiri City
36. Branch Office, Chiploon
37. Branch Office, Kudal
38. Divisional Office, Ichalkaranji
39. Branch Office, Ichalkaranji City
40. Branch Office, Jaisingpur
41. Branch Office, Varna Nagar
42. Branch Office, Gadhinglaj
43. Branch Office, Nader City
44. Branch Office, Parbhani
45. Branch Office, Latur
46. Divisional Office, Pune
47. Branch Office, Vira
48. Regional Office-II., Bam
49. Branch Office, Mahar
50. Branch Office, Alibagh
51. Branch Office, Ville Parle
52. Divisional Office, Solapur
53. Branch Officer, Panderpur
54. Branch Office, Usmanabad.

[No. 13011/1/92-HIC]

Y. P. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 1993

का. आ. 2321.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), नियमावली, 1976 के नियम-10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में (वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित) भारतीय साधारण बीमा निगम के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :

कम्पनी का नाम

नेशनल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

1. क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
2. शाखा कार्यालय, बाजपुर
3. शाखा कार्यालय, अलीगंज, लखनऊ
4. शाखा कार्यालय, मुरादाबाद
5. शाखा कार्यालय, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर

[संख्या 13011/1/92-हि.का.क.]

यशपाल गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 21st October, 1993

S.O. 2321.—In pursuance of Sub-rule (4) of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following Offices of the General Insurance Corporation of India (Under the Administrative Control of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs where of more than 80 per cent of staff have acquired working knowledge of Hindi.

Name of the Company : National Insurance Co. Ltd.,

1. Regional Office., Lucknow
2. Branch Office, Bajpur
3. Branch Office, Aliganj, Lucknow
4. Branch Office, Muradabad
5. Branch Office, Transport Nagar, Kanpur.

[No. 13011/1/92-HIC]

Y. P. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 1993

का. आ. 2322.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), नियमावली, 1976 के, नियम-10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में (वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित) भारतीय साधारण बीमा निगम के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :

कम्पनी का नाम :

दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

1. क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़
2. मण्डल कार्यालय I, जम्मू
3. मण्डल कार्यालय, II, जम्मू
4. मण्डल कार्यालय, पटियाला
5. मण्डल कार्यालय, राजपुरा
6. मण्डल कार्यालय, फिरोजपुर
7. शाखा कार्यालय, जलालाबाद
8. शाखा कार्यालय, नवाशहर
9. शाखा कार्यालय, जगसांव
10. शाखा कार्यालय, कठुआ
11. शाखा कार्यालय, आर. एस. पुरा
12. शाखा कार्यालय—जम्मू I
13. शाखा कार्यालय—II, जम्मू
14. शाखा कार्यालय—III, जम्मू
15. शाखा कार्यालय, उधमपुर
16. शाखा कार्यालय, राजौरी
17. शाखा कार्यालय, बटोट
18. शाखा कार्यालय—11, बम्बई
19. शाखा कार्यालय—12, बम्बई
20. शाखा कार्यालय, खरगोन
21. शाखा कार्यालय, सतना
22. शाखा कार्यालय, बिलासपुर
23. शाखा कार्यालय—2, रायपुर
24. प्रत्यक्ष अभिकर्ता शाखा, इंदौर
25. प्रत्यक्ष अभिकर्ता शाखा, भोपाल

[सं. 13011/1/92—हि.का.क.]

यशपाल गुप्ता, अवसर सचिव

New Delhi, the 21st October 1993

S.O. 2322.—In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for the Official purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following Offices of the General Insurance Corporation of India (Under the Administrative Control of Ministry of Finance Department of Economic Affairs) where of more than 80 per

cent of staff have acquired working knowledge of Hindi.

Name of the Company : The Oriental Insurance Co. Ltd.,

1. Regional Office, Chandigarh
2. Divisional Office-I, Jammu
3. Divisional Office-II, Jammu
4. Divisional Office, Patiala
5. Divisional Office, Rajpura
6. Divisional Office, Ferozpur
7. Branch Office, Jalalabad
8. Branch Office, Nava City
9. Branch Office, Jagraon
10. Branch Office, Kathua
11. Branch Office, R.S. Pura
12. Branch Office-I, Jammu
13. Branch Office-II, Jammu
14. Branch Office-III, Jammu
15. Branch Office, Udhampur
16. Branch Office, Rajouri
17. Branch Office, Batot
18. Branch Office-11, Bombay
19. Branch Office-12, Bombay
20. Branch Office, Khargaon
21. Branch Office, Satna
22. Branch Office, Bilaspur
23. Branch Office, Raipur
24. Direct Agent Branch, Indore
25. Direct Agent Branch, Bhopal.

[No. 13011/1/92-HIC]

Y. P. GUPTA, Under Secy.

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1993

का. आ. 2323.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सकारिश पर एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लि. पर 9 जुलाई, 1995 तक, म्यूनिसिपल सं. 5483 से 5494 पर 3-1/2 मंजली बिल्डिंग, जो घंटाघर चांदनी चौक और नई सड़क, दिल्ली-6 पर स्थित है, की अवलम्बिता पर लागू नहीं होंगे।

[सं. 15/12/88—बी. ओ. ए.]

राज्यलक्ष्मी, निदेशक

(Banking Division)

New Delhi, the 13th October, 1993

S.O. 2323.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act shall not apply to the Punjab Cooperative

Bank Ltd., till 9th July, 1995 in respect of the immovable property consisting of 3-1/2 storeyed building bearing Municipal No. 5483 to 5494/1 and situated at the corner of Ghantaghar, Chandni Chowk, and Nai Sarak, Delhi-6.

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 1993

का.आ. 2324.—बैंककारी विनियमन अधिनियम 1998 (1949 का 10) की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 के उपबंध का मोनाथ सेठ बैंक लि. पर 33 अक्टूबर 1993 तक उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहाँ तक इस बैंक से दिनांक 31 मार्च 1993 तक की स्थिति के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित लेखाओं और तुलनपत्र को निर्धारित ढंग से प्रकाशित करने और उसकी तीन प्रतियाँ भारतीय रिजर्व बैंक को 30 सितम्बर 1993 तक की बड़ाई हुई अवधि के अन्दर अन्दर विवरणियों के रूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

[सं. 15/8/93-बी.ओ.ए.]

के.के. मंगल, अवसर सचिव

New Delhi, the 14th October, 1993

S.O. 2324.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 31 of the said Act, shall not apply to the Kashi Nath Seth Bank Ltd. upto 31st October, 1993 in so far as it is required to publish the accounts and balance sheet as at 31st March, 1993 together with auditors' report in the prescribed manner and submit three copies thereof as returns to the Reserve Bank of India within the extended period upto 30th September, 1993.

[No. 15/8/93-BOA]

K. K. MANGAL, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 1993

का.आ. 2325.—मै. गजेबो इण्डस्ट्रीज ल. 135 डा. एनी बेसेन्ट रोड बोर्ली बम्बई-210098 को 56 37 000 रुपए (194370 अमरीकी डालर) के निर्यात आधार वाले 40 26 300 रुपए के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए एक अग्रिम लाइसेंस सं. पी/एन 1523846 दिनांक 7-12-92 मंजूर किया गया था जिसकी वैधता अवधि जारी करने की 2401 GI/93-2.

तारीख से 12 महीने थी। अब फर्म ने केवल आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस (सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति तथा विनियम प्रति दोनों) की दूसरी प्रति इस आधार पर प्रदान करने के लिए आवेदन किया है कि लाइसेंस खो गया है/गुम हो गया है। फर्म ने आवश्यक हलफनामा प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार पूर्वोक्त अग्रिम लाइसेंस को सीमाशुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत नहीं कराया गया था तथा उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया था और लाइसेंस के मद्दे बकाया लागत बीमा भाड़ा मूल्य 40 26 300 रुपए है। हलफनामों में इस आशय की एक घोषणा भी समाविष्ट की गई कि उक्त लाइसेंस का बाद में पता चलाने पर या उसके मिलने पर उसे निर्गम प्राधिकारी को लौटा दिया जायगा।

इस बात से संतुष्ट होने पर कि केवल आयातों के लिए मूल अग्रिम लाइसेंस (सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति तथा विनियम नियंत्रण प्रति दोनों) खो गया है अधोहस्ताक्षरी का यह निर्देश है आवेदक को केवल आयात के लिए दूसरा अग्रिम लाइसेंस (सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति और विनियम नियंत्रण प्रति) जारी कर दिया जाए। साथ ही विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के द्वारा 9 के उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्वारा केवल आयातों के लिए मूल अग्रिम लाइसेंस (सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति तथा विनियम नियंत्रण प्रति) को एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

[फा.सं. 01/81/40/1314/ए एम-93/डी ई एस-3/1960]

आर.के. सूद, उप महानिदेशक विदेश व्यापार
रुते महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

(Directorate General of Foreign Trade)

New Delhi, the 20th October, 1993

S.O. 2325.—M/s. Gazebo Industries Ltd., 135, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400098 were granted an Advance Licence No. P/L/1523846 dated 7th December, 1992 for a c.i.f. value of Rs. 40,26,300 with an export obligation of Rs. 56,37,000 (US Dollars 194370) with a validity of 12 months from the date of issue. Now the firm have applied for grant of duplicate of Advance Licence (Customs purpose copy and Exchange Control copy both) for the import only on the ground that the licence have been lost/misplaced. The firm have furnished necessary affidavit according to which the aforesaid Advance Licence was not registered with and Customs Authority and was not utilised at all and the balance CIF value against the licence is Rs. 40,26,300. A declaration has also been incorporated in the affidavit to the effect that if the said licence is traced or found later on, it will be returned to the issuing Authority.

On being satisfied that the Original Advance Licence (Customs Purpose copy and Exchange Control copy both) for imports only have been lost, the undersigned directs that duplicate Advance Licence (Customs Purpose copy and Exchange control copy) for import only should be issued to the applicant. I also, in exercise of the powers conferred in sub-clause (4) of Clause 9 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, hereby cancel the original Advance Licence (Customs purpose copy and Exchange control copy) for imports only.

[F. No. 01/81/40/1314/AM-93/DES-III/1960]

R. K. SOOD, Dy. Director Genl. of Foreign Trade
for Director Genl. of Foreign Trade

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 1993

का.प्र. 2326.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 5 के उपविनियम (6) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि निम्न विवरण वाले लाइसेंस/लाइसेंसों को उनके प्रागे वर्गीकृत की गई तारीख से रद्द कर दिया गया है।

लाइसेंस सं.	लाइसेंस धारी का नाम और पता	लाइसेंस में दिए गए प्रक्रम/वस्तु संबंध भारतीय मानक सहित	रद्द किए जाने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1251131	धातु आर्क इलेक्ट्रोड मोदी नगर	वेलिंग चक्कर हेतु आवरित इलेक्ट्रोड आई एस : 814 (पार्ट II) - 1974	1993-03-16
1971367	जन रोलिंग मिल्स, गाजियाबाद	संरचना इस्पात (मानक किस्म) आई एस : 226-1975	1993-02-16

[सं. सी एम जी/ 13 : 13]

एन. श्रीनिवासन, अपर महानिदेशक

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES,
CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

New Delhi, the 12th October, 1993

S.O.2326:—In pursuance of sub-regulation (6) of regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification), Regulation 1988, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the licence(s) particulars of which are given below have been cancelled with effect from the date indicated against each:

SCHEDULE

Licence No.	Name and Address of the licensee	Article/Process with relevant Indian Standard covered by the licence cancelled	Date of cancellation
1	2	3	4
1251131	Modi Arc Electrodes, Modi Nagar	Covered electrodes for welding sheets— IS : 814 (Part II)-1774	1993-03-16
1971367	Jain Rolling Mills, Ghaziabad	Structural steel (Standard Quality)— IS : 226-1775	1993-02-16

[No. CMD/13 : 13]

N. SRINIVASAN, Addl. Director Gen.

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 1993

का.प्र. 2327.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम 1988 के विनियम 5 के उपविनियम (6) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि निम्न विवरण वाले लाइसेंस/लाइसेंसों को उनके प्रागे वर्गीकृत की गई तारीख से रद्द कर दिया गया है।

लाइसेंस सं.	लाइसेंसधारी का नाम और पता	लाइसेंस में दिए गए प्रक्रम/वस्तु सम्बंध भारतीय मानक सहित	रद्द किए जाने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
0692156	विल्ली स्पान पाइप 12/1 मील का पथर, मथुरा रोड फरीदाबाद-120001	आई एस : 458-1938 आर सी सी पाइप	93-01-27
1259753	इंडस्ट्रियल प्रॉडक्ट्स प्लाट नं. 4 इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कालोनी कुंजपुरा रोड करनाल (हरियाणा)	आई एस : 814 (पार्ट II) - 1974 इलेक्ट्रोड	93-02-16

1	2	3	4
1311830	हिमाचल कंडक्टर प्लाट नं. 36 बीर 37, सेक्टर-1, परबा, जिला सोलम (हि.प्र.)	आई एस : 398 (पार्ट I)-1976 ए ए सी चालक	93-02-16
1656460	एन.के. प्लास्टिक जी.डी. रोड, जालंधर छावनी	आई एस : 10840-1986 एच डी पी ई चालक	92-12-09
1662960	नेशनल कार्बन खोनमोह इंडस्ट्रियल एस्टेट श्रीनगर-191104	आई एस : 203-1984 शुष्क बैटरी	93-03-16
2013322	आरती स्टील रोलिंग मिल्स लि. गाजियाबाद	आई एस : 226-1975 संरचना इस्पात (मानक किस्म)	92-11-28

[सं. सी एम डी/13 : 13]

एन. श्रीनिवासन, अपर महानिदेशक

New Delhi, the 12th October, 1993

S.O. 2327—In pursuance of sub-regulation (6) of regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulation 1988, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the licence(s) particulars of which are given below have been Cancelled with effect from the date indicated against each:

SCHEDULE

Licence No. (CM/L-)	Name and Address of the licensee	Article/Process with relevant Indian Standard covered by licence Cancelled	Date of Cancellation
1	2	3	4
0692156	Delhi Spun Pipes, 12/1, Milestone, Mathura Road, Faridabad-121001.	IS : 458-1983, RCC pipes	1993-01-27
1259753	Industrial Products, Plot No. 4, Industrial Development Colony, Kunjpura Road, Kanai (Haryana)	IS : 814 (Part II)-1974 Electrodes	1993-02-16
1311830	Himachal Conductors Plot No. 36 & 37, Sector-I Parwanoo, Distt. Solan (H.P.)	IS : 398 (Part I)-1976 AAC conductors	1993-02-16
1311931	-do-	IS : 398 (Part II)-1976 ACSR conductor	1993-02-16
1656460	N.K. Plastic, G.T.Road, Jalandhar Cantt.	IS : 10840-1986 HDPE container	1992-12-09
1662960	National Carbon Co. Khonmoh Industrial Estate Srinagar-191104	IS : 203-1984 Dry batteries	1993-03-19
2013322	Aarti Steel Rolling Mills Ltd., Ghaziabad	IS : 226-1975 Structural steel (standard quality)	1992-11-28

[No. CMD/13 : 13]

N. SRINIVASAN, Addl. Director General

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1993

का. मा. 2328.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधि-भोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार नीचे

दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में वर्जित अधिकारी को, जो भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के पद के समतुल्य अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है जो अबसे सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के बारे में करने अधिकारों की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत उक्त अधिनियम द्वारा या उसके

अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा, नामतः—

सारणी

अधिकार का पता और पदनाम सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं

श्री डी. सी. सिन्हा, मुख्य विधि अधिकारी, मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड, रांची	रांची में मेटलर्जिकल एंड इंजी- नियरिंग कन्सल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (मेकन) के अथवा उसके द्वारा पट्टे पर लिये गये सभी स्थान।
--	--

[फा. सं. 10(8)/92-एच.एस.एम.]

श्रीमती मृदुल जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 8th October, 1993

S.O. 2328—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (4) of 1971 the Government of India in the Ministry of Steel hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the table below, being an Officer equivalent to the rank of gazetted officer of Government, to be estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officer by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the Table, namely :

TABLE

Address and designation of the Officer	Categories of the Public premises and local limits of jurisdiction
1	2
Chief Law Officer, Metallurgical & Engineering Consultants (Ind.a) Limited, Ranchi.	All premises belonging to or taken on lease by Metallurgical & Engineering consultants (India) Limited in Ranchi.

[F.No. 10(8)/92-HSM]

SMT. MRIDUL JAIN, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 1993

का. प्रा. 2329.—होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में, नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित व्यक्ति को स्तंभ (2) में उल्लिखित विश्वविद्यालय से निर्वाचित किया गया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, का. प्रा. 482(अ), तारीख 6 अगस्त, 1974 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)
"16. डा. प्रबीर चक्रवर्ती 11/8, देवी चौधरी रोड, कलकत्ता-700023	कलकत्ता विश्वविद्यालय।"

[सं. वी. 26018/15/87-होम्यो (सी. सी. एच.)

बी. सी. मेहता, डेस्क अधिकारी

पाद-टिप्पण : मूल अधिसूचना का. प्रा. सं. 482(अ), तारीख 6 अगस्त, 1974 द्वारा जारी की गई थी और बाद में उसका अधिसूचना सं. वी.-26018/15/87-होम्यो (सी. सी. एच.) (ii), तारीख 29 अगस्त, 1990 और अधिसूचना सं. वी. 26017/15/87-होम्यो (सी. सी. एच.) (ii), तारीख 27 जनवरी, 1992 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 15th October, 1993

S.O. 2329—Whereas in pursuance of the provisions of clause (b) of sub-section (i) of section 3 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the person mentioned in column (1) of the Table below has been elected from the University mentioned in Column (2).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning, Department of Health published vide S.O. 482(E), dated the 6th August, 1974, namely :—

In the Table to the said notification, for serial number 16 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :

1	2
"16 Dr. Prabir Chakraborti 11/8, Debi Chowdhury Road, Calcutta-700 023.	University of Calcutta."

[No. V-26018/15/87-Homoeo (CCH)]

B.C. MEHTA, Desk Officer

Foot Note:

The original notification was issued vide No. S.O. 482(E) dated the 6th August, 1974, and subsequently amended by notification No. V-26018/15/87-Homoeo (CCH)(ii) dated 29th August, 1990 and notification No. V-26017/15/87-Homoeo (CCH)(ii) dated 27th January, 1992.

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 1993

का.आ. 2330—केन्द्रीय सरकार, होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1973 (1973 का 59) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद् में परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में “आंध्र प्रदेश” शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 3 ग और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4
होमियोपैथिक मेडिसिन और सर्जरी में स्नातक	बी. एच. एम. एस.	1990 से आगे	

[मं. बी-27021/12/84-होमियो]
बी. सी. मेहता, डेस्क अधिकारी

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 2, खंड 1 में का. आ. सं. 76 तारीख 20 दिसम्बर, 1993 द्वारा प्रकाशित हुई थी और तत्पश्चात् उसमें

का.आ.सं. 3325 तारीख 4-11-1978
का.आ.सं. 1517 तारीख 26-2-1983
का.आ.सं. 1481 तारीख 12-3-1983
का.आ.सं. 3099 तारीख 21-6-1985
का.आ.सं. 2048 तारीख 24-3-1986
का.आ.सं. 2270 तारीख 24-5-1986
का.आ.सं. 2449 तारीख 1-8-1990
का.आ.सं. 2501 तारीख 1-8-1990
का.आ.सं. 2502 तारीख 21-8-1990
का.आ.सं. 710 तारीख 20-2-1992
का.आ.सं. 891 तारीख 5-3-1992
का.आ.सं. 1210 तारीख 23-4-1992
का.आ.सं. 2669 तारीख 24-9-1992
का.आ.सं. 978 तारीख 28-4-1993

द्वारा संशोधन किए गए और भारत के राजपत्र, भाग 2 खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई।

New Delhi, the 18th October, 1993

S.O. 2330.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of section 13 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government after consulting the Central Council of Homoeopathy hereby makes the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, namely :—

In the said Schedule, under the head ‘Andhra Pradesh, under Serial number 3C and the entries relating thereto, the following entries shall be added namely :—

1	2	3	4
Bachelor in Homoeopathic Medicine and Surgery	B.H.M.S.	From 1990 onwards.	

[No. V-27021/12/84-Homoco]
B.C. MEHTA, Desk Officer

Foot Note:

The Principal Notification was published in No. S.O. 76 dated the 20th December, 1973 in Gazette of India Extraordinary Part II Section 1 and subsequently amended vide

S.O. 3325 dated 4-11-1978,
S.O. 1517 dated 26-2-1983,
S.O. 1481 dated 12-3-1983,
S.O. 3099 dated 21-6-1985,
S.O. 2048 dated 24-3-1986,
S.O. 2270 dated 24-5-1986,
S.O. 2449 dated 1-8-1990,
S.O. 2501 dated 1-8-1990,
S.O. 2502 dated 24-8-1990,
S.O. 710 dated 20-2-1992,
S.O. 891 dated 5-3-1992,
S.O. 1210 dated 23-4-1992
S.O. 2669 dated 24-9-1992.

published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii).

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संस्वालय

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1993

का. आ. 2331.—केन्द्रीय सरकार ने पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संस्वालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2852 तारीख 10 नवम्बर, 1990 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गयी थी, पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन विछाने के प्रयोजनार्थ, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपन आशय की घोषणा की थी :

और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 15 नवम्बर, 1990 को उपलब्ध करा दी गयी थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है :

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में

उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विलयनों से मुक्त, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

तहसील : जोधपुर	जिला : जोधपुर	राज्य : राजस्थान	क्षेत्रफल		
गांव का नाम	खसरा नं.	हैक्टर	आर	वर्गमीटर	
1	2	3	4	5	
सीकपुरा	280	00	19	87	

[संख्या : आर-31015/49/93-ओ. आर.-I]

कुलदीप सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 27th October, 1993

S.O. 2331.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 2855, dated the 10th November, 1990 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum;

And whereas copies of the Gazette notification has been made available to the public on the 15th November, 1990;

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired.

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited.

SCHEDULE

Tehsil : Jodhpur District : Jodhpur State : Rajasthan

Area				
Name of Village	Khasra No.	Hectare	Are	Centj-are
1	2	3	4	5
Sikanpura	280	0	19	87

[No. R-31015/49/93-O.R. I]

KULDIP SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 1993

का. मा. 2332.—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. मा. 2853 तारीख 10 नवम्बर, 1990 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गयी थी, पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन बिछाने के योजनार्थ, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी:

और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 15 नवम्बर, 1990 को उपलब्ध करा दी गयी थी:

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी थी।

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए:

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है:

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विलयनों से मुक्त, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

तहसील : पाली	जिला : पाली	राज्य : राजस्थान	क्षेत्रफल		
गांव का नाम	खसरा नं.	हैक्टर	आर	वर्गमीटर	
1	2	3	4	5	
भांडल	380	00	66	82	
मालराई	328	00	17	58	
	299	00	53	58	
कोरवा	49	00	49	54	
	108	00	49	54	
गुडा एण्डला	24	00	07	78	
	43	00	15	28	
	44	00	16	42	
	47	00	03	76	
	48	00	30	53	
	52	00	36	29	
	53	00	10	66	
	56	00	06	63	
	59	00	32	26	
	60	00	26	52	
	61	00	25	63	

1	2	3	4	5
	62	00	18	72
	63	00	14	12
	64	00	12	96
	74	00	21	89
	75	00	24	48
	77	00	27	60
	78	00	09	22
	79	00	24	48
	80	00	32	26
	342	00	88	13
	346	00	11	81
	374	00	14	11
	675	00	36	58
	678	00	28	80
	659	00	17	57
	660	00	32	26
	663	00	18	72
	664	00	18	72
	667	00	36	87
	671	00	07	49
	675	00	51	55
	683	00	22	47
	1469	00	17	57
	1478	00	14	11
	1480	00	48	68
	1484	00	29	67
	1492	00	31	10
	1493	00	31	68
	1496	00	40	61
	1499	00	50	11
	1578	00	20	74
कूरना	1423	01	30	46
	421	00	57	31
	419	00	01	73
	290	00	18	72
बासा	192	02	02	46
रामावास	346	00	21	31
बिदरू	291/1	01	13	93
	243/4	01	26	95
मोरिया	6/1	01	68	80
सोनाई लाखा	142	00	13	42
सिन्गारी	98	00	29	96
	97	01	24	44
	86	00	75	76
	84	00	29	39
	80	01	13	78
	79	00	01	15
बीसली पटेलान	140	00	44	64
	141	00	79	78
	142	00	17	57
	134	00	28	80
	143	00	13	55
	133	00	24	77

New Delhi, the 27th October, 1993

S.O. 2332.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 2853, dated the 10th November, 1990 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum ;

And whereas copies of the Gazette notification has been made available to the public on the 15th November, 1990 ;

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government ;

And whereas the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land hereby directs that the right of user in the said lands shall hereby acquired.

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Indian oil Corporation Limited.

Schedule

Tehsil : Pali	District : Pali	State : Rajasthan		
Area				
Name of Village	Khasra No.	Hec-tare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Mandal	380	00	66	82
Balrai	328	00	17	58
	299	00	53	58
Keerwa	49	00	49	54
	108	00	49	54
Gurha Emdla	24	00	07	78
	43	00	15	28
	44	00	16	42
	47	00	03	76
	48	00	30	53
	52	00	36	29
	53	00	10	66
	56	00	06	63
	59	00	32	26
	60	00	26	52
	61	00	25	63
	62	00	18	72
	63	00	14	12
	64	00	12	96
	74	00	21	89
	75	00	24	48
	77	00	27	66
	78	00	09	22
	79	00	24	48

[संख्या : प्रार.-31015/49/93-ओ. प्रार.-I]

कुलदीप सिंह, प्रवर सचिव

1	2	3	4	5
	80	00	32	26
	342	00	88	13
	346	00	11	81
	374	00	14	11
	675	00	36	58
	678	00	28	80
	659	00	17	57
	660	00	32	26
	663	00	18	72
	664	00	18	72
	667	00	36	87
	671	00	07	49
	675	00	51	55
	683	00	22	47
	1469	00	17	57
	1478	00	14	11
	1480	00	48	68
	1484	00	29	67
	1492	00	31	10
	1493	00	31	68
	1496	00	40	61
	1499	00	50	11
	1578	00	20	74
Koorna	1423	01	30	46
	421	00	57	31
	419	00	01	73
	290	00	18	72
Bala	192	02	02	46
Roopawas	346	00	21	31
Beethoo	291/1	01	13	93
	243/4	01	26	95
Moriya	6/1	01	68	80
Sonai Lakha	142	00	13	42
Singari	98	00	29	96
	97	01	24	44
	86	00	75	76
	84	00	29	39
	80	01	13	78
	79	00	01	15
Neembli Patelan	140	00	44	64
	141	00	79	78
	142	00	17	57
	134	00	28	80
	143	00	13	55
	133	00	24	77

[No. R-3015/49/93—O.R.—I]
KULDIP SINGH, Under Secy.

मई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1993

का. प्रा. 2333.—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. प्रा. 2854 तारीख 10 नवम्बर, 1990 द्वारा जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गयी थी, पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन विधान के प्रयोजनार्थ, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आदेश की घोषणा की थी;

और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 15 नवम्बर, 1990 को उपलब्ध करा दी गयी थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जन करने की घोषणा करती है;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लेती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विस्त्वगर्भों से मुक्त, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

3.				
तहसील : बाली	जिला : पाली	राज्य : राजस्थान		
क्षेत्रफल				
गांव का नाम	खसरा नं.	हैक्टर	घार	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
कोरापुरा	57	00	20	16
	58	00	28	54
	59	00	29	70
	60	00	18	90
ग्रणी	872	00	05	40

[संख्या : घार.-31015/49/93-ओ. घार.-I]

कुलदीप सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 27th October, 1993

S.O. 2333.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 2854, dated the 10th November, 1990 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum;

And whereas copies of the Gazette notification has been made available to the public on the 15th November, 1990;

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central

Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired.

अनुसूची

And further in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited;

Schedule

Tehsil : Bali		District : Pali		State : Rajasthan	
			Area		
Name of Village	Khasra No.	Hec-tare	Are	Centiare	
1	2	3	4	5	
Kerapura	57	00	20	16	
	58	00	28	54	
	59	00	29	70	
	60	00	18	90	
Dhany	872	00	05	40	

[No. R-31015/49/93-OR-I]
KULDIP SINGH, Under Secy

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1993

का.आ. 2334 --- केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज प्राप्ति लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2855 तारीख 10 नवम्बर, 1990 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गयी थी, पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 15 नवम्बर, 1990 को उपलब्ध करा दी गयी थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विलगनों से मुक्त, इच्छित और न्यायोचित विनिर्देश में निहित होगा ।

2401 GI/93-3.

तहसील : देसूरी	जिला : पाली	राज्य : राजस्थान		
क्षेत्रफल				
गाँव का नाम	खसरा नं.	हेक्टर	आर	वर्गमीटर
1	2	3	4	5
रानी खुर्द	270	00	22	60
	268	00	10	36
	269	00	07	85
	201	00	01	69
	202	00	01	69
	204	00	09	29
	203	00	26	92
	197	00	28	50
	196	00	31	75
195	00	19	73	
रानीकला	1198	00	00	72
	1202	00	09	00
	1188	00	00	16
	788	00	27	40
	779	00	05	76
पादरली	72	00	12	24
पूनाडिया	467	00	29	06
दूदवर	121	00	06	50
	119	00	10	94

[संख्या आर.- 31015/49/93-ओ.आर. I]

कुलदीप सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 27th October, 1993

S.O. 2334.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 2855, dated the 10th November, 1990 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum ;

And whereas copies of the Gazette notification has been made available to the public on the 15th November, 1990 ;

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government ;

And whereas the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the rights of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited :

Schedule

Tehsil : Desuri District : Pali State : Rajasthan				
Area				
Name of Village	Khasra No.	Hec-tare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Ranikhurd	270	00	22	60
	268	00	10	36
	269	00	07	85
	201	00	01	69
	202	00	01	69
	204	00	09	29
	203	00	26	92
	197	00	28	50
	196	00	31	75
	195	00	19	73
RaniKalan	1198	00	00	72
	1202	00	09	00
	1188	00	00	16
	788	00	27	40
	779	00	05	76
Padarali	72	00	12	24
Punadiya	467	00	29	06
Doodawar	121	00	06	50
	119	00	10	94

[No. R-3/015/49-93-OR-I]

KULDIP SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1993

का. प्रा. 2335--केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.प्रा. 3057 तारीख 17 नवम्बर, 1990 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गयी थी, पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ अन्ततः की तारीख 22 नवम्बर, 1990 को उपलब्ध करा दी गयी थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार की अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करते के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाय;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करना है ;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी बिन्दुओं से मुक्त, इन्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

तहसील : रायपुर	जिला : पाली	राज्य : राजस्थान		
क्षेत्रफल				
गांव का नाम	खसरा नं०	हेक्टर	घार	वर्गमीटर
1	2	3	4	5
शोलिया	66	00	05	46
	119	00	04	10
	950/2	00	07	92
मानपुरा	599	00	00	20
	675	00	07	80
कुरासिया सराधना	66	00	04	80
	285	00	05	40
	263	00	03	24
	262	00	05	76
	261	00	03	96
	259	00	04	14
	205	00	07	20
	200	00	01	08
	204	00	03	24
	210	00	00	20
	203	00	09	52
	202	00	01	28
	196	00	07	62
	195	00	02	00
	189	00	04	50
	188	00	02	52
	190	00	01	07
	187	00	00	60
	कोरगढ़	228	00	11
227		00	14	04
232		00	02	00
225		00	24	64
226		00	12	60
86		00	02	53
87		00	01	44
88		00	06	48
91		00	06	48
93		00	01	44
95		00	04	32
96		00	01	40
97		00	03	70

1	2	3	4	5
शेरगढ़ (जारी)	98	00	01	60
	99	00	06	10
	100	00	03	96
	101	00	01	50
	102	00	05	76
	103	00	12	00
	105	00	02	52
	107	00	03	21
	108	00	06	84
	110	00	01	41
	111	00	01	41
	112	00	02	16

[सं. : आर-31015/49/93-ओ. आर.-I]

कुलदीप सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 27th October, 1993

S.O. 2335.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 3057, dated the 17th November, 1990, published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum ;

And whereas copies of the Gazette notification has been made available to the public on the 22nd November, 1990;

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government ;

And whereas the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired.

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the rights of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited :

Schedule

Tehsil : Raipur District : Palit State : Rajasthan.				
Name of Village	Area			
	Khasra No.	Hectare	Acre	Centiare
1	2	3	4	5
Dholiya	66	00	05	46
	119	00	04	10
	950/2	00	07	92

1	2	3	4	5
Manpura	599	00	00	20
	675	00	07	80
Kurania	66	00	04	80
Saradhana	265	00	05	40
	263	00	03	24
	262	00	05	76
	261	00	03	96
	259	00	04	14
	205	00	07	20
	200	00	01	08
	204	00	03	24
	210	00	00	20
	203	00	09	52
	202	00	01	28
	196	00	07	62
	195	00	02	00
	189	00	04	50
	188	00	02	52
	190	00	01	07
	187	00	00	60
Shergarh	208	00	11	52
	227	00	14	04
	222	00	02	00
	225	00	24	64
	226	00	12	60
	86	00	02	52
	87	00	01	44
	88	00	06	48
	91	00	05	48
	93	00	01	44
	95	00	04	32
	96	00	01	40
	97	00	03	20
	98	00	01	60
	99	00	06	40
	100	00	03	96
	101	00	04	50
	102	00	05	76
	103	00	12	00
	105	00	02	52
	107	00	03	24
	108	00	06	84
	110	00	01	44
	111	00	01	44
	112	00	02	16

[No. R-31015/49/93-OR-I]

KULDIP SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1993

का. भा. 2336.—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पदार्थ खाद्य (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संजाल की अधिसूचना संख्या का. भा. 698 तारीख 28 फरवरी, 1992 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गयी थी, पेट्रोलियम के परिवहन, के लिये वाहपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अधीन के अपने प्राथम की अधिसूचना की थी;

और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 20 मार्च, 1992 को उपलब्ध करा दी गयी थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विस्मयनों से मुक्त, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

तहसील : जयपुर जिला : जयपुर राज्य : राजस्थान

क्षेत्रफल

गांव का नाम	खसरा नं.	हैक्टर	आर	बर्गमीटर
1	2	3	4	5
जामडोली	172	00	04	10
सुमेल	43/731	00	08	32
	23/723	00	02	10
जयसिंहपुरा खोर	2085	00	12	10

[संख्या : आर-31015/49/93-ओ. प्रार.1]

कुलदीप सिंह, भयर सचिव

New Delhi, the 27th October, 1993

S.O. 2336.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 696, dated the 29th February, 1992 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3 Sub-section (ii), issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum;

And whereas copies of the Gazette notification has been made available to the public on the 26th March, 1992.

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the rights of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited:

Schedule

Tehsil : Jipur	District : Jaipur	State : Rajasthan	Area		
Name of Village	Khasra No.	Hec-tare	Ac	Centi-are	
1.	2.	3.	4.	5.	
Jamdoli	172	00	04	10	
Sumel	43/731	00	08	32	
	23/723	00	02	10	
Jaisinghpura Khor	2085	00	12	10	

[No. R-31015/49/93-OR-I]

KULDIP SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1993

आ.सं. 2337.—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जैसे हमने इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अर्जित करने की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संजाल की अधिसूचना संख्या आ.सं. 697 तारीख 29 फरवरी, 1992 द्वारा, जो भारत के राष्ट्रपति, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गयी थी, पेट्रोलियम के परिवहन के निम्न पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 26 मार्च, 1992 को उपलब्ध करा दी गयी थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है:

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है।

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विस्मयनों से मुक्त, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

धनुसूची

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1993

तहसील : जमुवा रामगढ़	जिला : जयपुर	राज्य : राजस्थान		
क्षेत्रफल				
गांव का नाम	खसरा नं०	हेक्टर	आर०	वर्ग-मीटर
1	2	3	4	5
नटाटा	322	00	10	80

[संख्या आर-31015/49/93-ओ०आर-1]

कुलदीप सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 27th October, 1993

S.O. 2337.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 697, dated the 29th February, 1992 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum;

And whereas copies of the Gazette notification has been made available to the public on the 26th March, 1992;

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired.

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited;

SCHEDULE

Tehsil : Jamua Ramgarh District : Jaipur State : Rajasthan

Area				
Name of Village	Khasra No.	Hec-tare	Aro	Centi-are
1.	2.	3.	4.	5.
Natata	322	00	10	80

[No. R 31015/49/93 O.R.-I]

KULDIP SINGH, Under Secy.

का०आ० 2337:—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संस्थापन की अधिसूचना संख्या का०आ० 698 तारीख 29 फरवरी, 1992 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गयी थी, पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ, उक्त अधिसूचना में संलग्न धनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अधिनियम के अधीन आगम की घोषणा की थी :

और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 26 मार्च, 1992 को उपलब्ध करा दी गयी थी :

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसारण में संलग्न प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है :

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न धनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम किया जाए :

इसके केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न धनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है :

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी ब्रिस्तानों से मुक्त, एडिचन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

धनुसूची

तहसील : कोटपुगली	जिला : जयपुर	राज्य : राजस्थान		
क्षेत्रफल				
गांव का नाम	खसरा नं०	हेक्टर	आर	बर्ग-मीटर
1	2	3	4	5
पायटा	2352	00	23	76
पाचरेड़ी	132	00	00	65
	209	00	25	56
पुतली	60	00	09	72
रघुनाथपुरा	422	00	02	88
	440	00	01	44
मुम्बरपुरा	197	00	22	04
खडखड़ी	380	00	00	10
गोधर्गमपुरा	1023	00	14	40
	1442	00	09	00
सांगदेवा	608	00	02	72
	511	00	07	92

1	2	3	4	5
	546	00	17	10
	611	00	04	32
मोरदा	426	00	04	14
	471	00	18	36
	523	00	02	00

[संख्या : आर-31015/49/93-ओ.आर.-I]

कुलदीप सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 27th October, 1993

S.O. 2338.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 693, dated the 29th February, 1992 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum ;

And whereas copies of the Gazette notification has been made available to the public on the 26th November, 1992;

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired.

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the rights of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited :

SCHEDULE

Tehsil : Kotputli	District : Jaipur	State : Rajasthan	Area		
Name of Village	Khasra No.	Hec-tare	Are	Centi-are	
1	2	3	4	5	
Paota	2352	00	23	76	
Pathredi	132	00	00	65	
	209	00	25	56	
Putli	60	00	09	72	
Raghunathpura	422	00	02	88	
	440	00	01	44	
Sundarpura	197	00	22	04	
Khadkhadi	360	00	00	10	
Goverdhanpura	1023	00	14	40	
	1442	00	09	09	

1	2	3	4	5
Sangteda	508	00	02	72
	511	00	07	92
	546	00	17	10
	641	00	04	32
Morda	426	00	04	14
	471	00	18	36
	523	00	02	00

[No. R 31015/49/93 O.R.-I]

KULDIP SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1993

कां.मां. 2339:—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज गैस लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.मां. 699 तारीख 29 फरवरी, 1992 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गयी थी, पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी :

और राजपत्रित अधिसूचना को प्रतियां जनता को तारीख 26 मार्च, 1992 को उपलब्ध करा दी गयी थी :

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसारण में तत्काल प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है :

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए :

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जन करने की घोषणा करती है ;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विल्लंपनों से मुक्त, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होना ।

अनुसूची

तहसील : बिराट नगर	जिला : जयपुर	राज्य : राजस्थान	क्षेत्रफल		
गांव का नाम	अंतरा.सं.		हेक्टर	घ.अ.	वर्गमीटर
1	2		3	4	5
जवानपुरा	1097		00	18	36
बागवांस महीरम	1274		00	02	30
भाबरू	854		00	00	52
भालिया	3494		00	01	44
	3517		00	15	84

[संख्या आर-31015/49/93-ओ.आर.-I]

कुलदीप सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 27th October, 1993

S.O. 2339.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 699, dated the 29th February, 1992 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum ;

And whereas copies of the Gazette notification has been made available to the public on the 26th March, 1992 :

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government ;

And whereas the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired.

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited ;

Schedule

Tehsil : Viratnagar		District : Jaipur		State : Rajasthan	
Name of Village	Khasra No.	Area			
		Hec-tare	Are	Centi-are	
1	2	3	4	5	
Jawanpura	1097	00	18	36	
Bagawas Ahiran	1274	00	02	30	
Bhabaru	854	00	00	52	
Aantela	3494	00	01	44	
	3517	00	15	84	

[No. R 31015/49/93 O.R.-I]
KULDIP SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1993

का.प्र. 2340.—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पदार्थ सार्वजनिक (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.प्र. 700 तारीख 29 फरवरी, 1992 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गयी थी, पेट्रोलियम के परिवहन के निम्न पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अर्जों का धोखा की गयी थी;

और राजपत्रित अधिसूचना के प्रतियाँ जनता की तारीख 26 मार्च 1992 को उपलब्ध करा दी गयी थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सश्रम अधिकारी ने केन्द्रीय सरकार की अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाय;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विस्तारों से मुक्त, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

तहसील : शाहपुरा		जिला : जयपुर		राज्य : राजस्थान	
गांव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल			
		हेक्टर	अर	वर्गमीटर	
1	2	3	4	5	
शाहपुरा	5073	00	06	15	
	5080/5637	00	05	04	
काट	133	00	09	19	
मनोहरपुर	7804	00	26	28	
	7897	00	22	32	
	8142	00	09	40	
	8147	00	19	74	
	3279/8220	00	00	92	
	7926	00	08	82	
लाखनी	106	00	00	10	
	177	00	06	04	
	180	00	10	98	
निठारा	796	00	07	10	
देवन	514/2897	00	01	41	
जोसे खुद रुक	983	00	07	20	
बिजानपुरा	1034	00	07	35	
	1200	00	03	24	

[संख्या आर 31015/49/93-आ धारा-1]

कुलदीप सिंह, अधर सचिव

New Delhi, the 27th October, 1993

S.O. 2340.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 700, dated the 29th February, 1992 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire

the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum ;

And whereas copies of the Gazette notification has been made available to the public on the 26th March, 1992 ;

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government ;

And whereas the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited;

Schedule

Tehsil : Shahpura	District : Jaipur	State : Rajasthan	Area		
Name of Village	Khasra No.		Hec-tare	Acre	Centi-are
1	2		3	4	5
Shahpura	5073		00	06	15
	5080/5637		00	05	04
Kant	133		00	09	19
Manoherpur	7804		00	26	28
	7897		00	22	32
	8142		00	08	40
	8147		00	19	74
	3279/8220		00	00	92
	7926		00	08	82
Lakhnee	106		00	00	10
	177		00	08	04
	180		00	10	93
Neethana	796		00	07	10
Davan	514/2897		00	01	44
Jaaje Khurd	983		00	07	20
urf Vishanpura	1034		00	07	35
	1200		00	03	24

[No. R 31015/49/93 O.R.-J]

KULDIP SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1993

का. था. 2341.—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पदार्थ-नाहन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. था. 701 तारीख 29 फरवरी, 1992 द्वारा, जो भारत. राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, पेट्रोलियम के परिवहन

के लिये पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने पक्ष की घोषणा की थी;

और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 26 मार्च 1992 को उपलब्ध करा दी गयी थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में उक्त अधिकारी ने केन्द्रीय सरकार की अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 4 विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जन करने की घोषणा करती है।

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी वित्तगणों से मुक्त इन्डियन अयल कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

तहसील : धामेर	जिला : जयपुर	राज्य : राजस्थान	क्षेत्रफल		
गाँव का नाम	खसरा न.		हेक्टर	घार	वर्गमीटर
1	2		3	4	5
अमोन	4793		00	00	80
	5267		00	03	96
	5268		00	01	08
	5287		00	00	45
खोश मीठा	28		00	01	30
	292		00	08	89
	300		00	03	70
	915		00	04	15
	1231		00	02	45
म्यानी	137		00	11	20
	162/2		00	00	60
रायपुर उर्फ दायाबाबा	76		00	07	90
	77		00	21	70
कायबाद कला गुप्त खर्क	178/201		00	01	44
जयलपुरा	159		00	38	30
अनी	56		00	11	35
कृष्ण	760		00	02	30
दुध	214		00	12	60
	216		00	04	68
	231		00	07	60
	233		00	17	05
	231		00	05	45
	235		00	03	90
	239		00	60	60
	240		00	11	15

1	2	3	4	5
245		00	08	10
246		00	08	85
248		00	12	70
250		00	23	20
252		00	00	45
253		00	05	05
254		00	02	50
258		00	00	50
306		00	07	30
327		00	03	40
328		00	03	45
329		00	06	05
331		00	12	50
345		00	03	65
346		00	03	85
347		00	02	15
351		00	04	25
353		00	16	15
354		00	01	60
364		00	03	35
366		00	05	40
367		00	00	90
368		00	07	75
369		00	04	10
370		00	00	70
371		00	03	10
372		00	00	50
373		00	04	15
390		00	04	85
लक्ष्मिना	825	00	14	94
प्रबरोल	1036	01	03	00
लाखेर	70	01	80	45

[संख्या आर-31015/49/93-जी आर-I]

कुलदत्त सिंह, भवर सचिव

New Delhi, the 27th October, 1993

S.O. 2341.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 701 dated the 29th February, 1992 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum ;

And whereas copies of the Gazette notification has been made available to the public on the 26th March, 1992 ;

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government ;

And whereas the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired ;

2401 GI/93—4

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired.

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited;

Schedule

Tehsil : Amber District : Jaipur State : Rajasthan

Name of Village	Khasra No.	Area		
		Hec-tare	Acre	Centi-are
1	2	3	4	5
Amber	4793	00	00	80
	5267	00	03	96
	5268	00	01	08
	5287	00	00	45
Khora Meena	28	00	01	30
	292	00	08	80
	300	00	03	70
	945	00	04	15
	1231	00	02	45
Syarl	137	00	11	20
	162/2	00	00	60
Rampura urf	76	00	07	90
Banyawala	77	00	21	70
Kalwar Kalan & Khurd	178/291	00	01	44
Jugalpura	159	00	38	30
Ani	56	00	11	35
Kukas	760	00	02	30
Dhand	214	00	12	60
	216	00	04	05
	231	00	07	60
	233	00	17	05
	234	00	05	45
	235	00	03	90
	239	00	10	60
	240	00	11	15
	245	00	08	10
	246	00	08	85
	248	00	12	70
	250	00	23	20
	252	00	00	45
	253	00	05	05
	254	00	02	50
	258	00	00	50
	307	00	07	30
	327	00	03	40
	328	00	03	45
	329	00	06	05
	331	00	12	50
	345	00	03	65
	346	00	03	85
	347	00	02	15
	351	00	04	25
	353	00	16	15

1	2	3	4	5
Daund (Contd.)	354	00	01	60
	364	00	03	35
	366	00	05	40
	367	00	00	90
	368	00	07	75
	369	00	04	10
	370	00	00	70
	371	00	03	10
	372	00	00	50
	373	00	04	15
	390	00	04	85
Labana	625	00	14	94
Achrol	1036	01	03	00
Lakher	70	01	80	45

[No. R-31015/49/93 O.R-I]
KULDIP KINGH, Under Secy.

मई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1993

पा.पा. 2342--केन्द्रीय सरकार ने, पैट्रोलियम और खनिज पार्श्व साधन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.पा. 702 तारीख 29 फरवरी, 1992 द्वारा, जो भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गयी थी, पैट्रोलियम के परिवहन के लिये वायुपलावन विद्युत के प्रसारणार्थ, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने प्राणय का घोषणा की थी;

और सम्बन्धित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 26 मार्च, 1992 को उपलब्ध करा दी गयी थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने संबंधित सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बावजूद सभी दिवसों में से नुकन, लिमिटेड आयात कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

सहस्रों : बहरोड़ जिला : अनवर राज्य : राजस्थान

गांव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
		हैक्टर	वर्ग मीटर	
1	2	3	4	5
सांसेड़ी	401	00	05	04
	722	00	08	84
	937	00	04	14

1	2	3	4	5
	968	00	09	90
	1041	00	00	38
गूठी	2083	00	13	68
फाली पहाड़ी	25	00	04	32
कल्याणपुरा	491	00	01	17
जैनपुर बास	884	00	04	32
मगला हन्ध	53	00	41	04
	293	00	02	88
फोलिता राबड़	121	00	01	02
	122	00	05	76
	123	00	09	00
	127	00	03	10
कांकर	579	00	05	10
	929	00	08	28
	1116	00	00	80
शिमला	59	00	02	40
	60	00	07	92
	61	00	11	52
	65	00	43	56
	70	00	02	60
	71	00	20	16
	75	00	12	40
	193	00	12	24
	194	00	04	50
	195	00	03	08
	196	00	00	72
	266	00	10	26
	270	00	00	98
	271	00	07	88
	272	00	07	92
	273	00	00	50
	275	00	00	80
	276	00	00	24
	278	00	04	78
	279	00	06	24
	281	00	04	48
	282	00	04	48
	290	00	11	28
	291	00	01	40
	299	00	00	08
	301	00	06	04
	302	00	09	00
	305	00	13	50
	70/432	00	16	75
	271/461	00	03	60
बेलनी	254	00	00	96
	255	00	01	98
	257	00	18	90
	260	00	05	08
	261	00	12	96
	268	00	27	00
	270	00	15	12

1.	2.	3.	4.	5	1	2	3	4	5
बेलन:	281	00	21	06	कोसिला सांगा	663	00	00	36
	282	00	00	78		664	00	15	12
	284	00	11	16		665	00	01	00
	285	00	05	94		674	00	00	60
	328	00	18	00		675	00	15	84
	330	00	18	90		677	01	01	00
	343	00	06	12		678	00	06	48
	344	00	12	96		292/775	00	00	80
	345	00	12	06		292/776	00	04	32
	484	00	12	96	तलवड़ सरबिलन्द	222	00	01	08
	487	00	14	04	मोमनपुर	223	00	05	94
	344/577	00	02	02		224	00	06	84
						225	00	06	84
कोसिला सांगा	231	00	00	72		226	00	05	04
	232	00	12	10		227	00	06	12
	233	00	07	20		228	00	04	86
	237	00	21	92		229	00	00	84
	238	00	03	08		234	00	07	20
	239	00	10	80		237	00	11	20
	240	00	00	90		238	00	12	48
	248	00	17	10		241	00	02	24
	251	00	02	80		242	00	00	96
	252	00	39	06		254	00	05	04
	253	00	00	96		255	00	02	88
	272	00	11	16		256	00	02	88
	275	00	11	16		271	00	09	72
	276	00	10	80		272	00	06	84
	282	00	05	22		273	00	12	24
	292	00	11	16		1377	00	08	82
	293	00	00	80		1378	00	09	00
	465	00	06	12		1396	00	11	88
	466	00	08	28		1397	00	22	86
	467	00	01	44		1403	00	17	82
	468	00	10	26		1423	00	15	12
	522	00	05	04		1425	00	15	30
	523	00	02	70		1427	00	04	00
	527	00	08	82		1428	00	06	88
	528	00	10	26		1429	00	10	00
	530	00	01	44		1431	00	03	90
	562	00	00	18		1432	00	14	40
	563	00	05	04		1434	00	01	08
	564	00	09	54		1435	00	02	88
	565	00	02	34		1396/1946	00	09	18
	613	00	05	58		1432/1997	00	00	32
	615	00	11	52					
	616	00	02	16					
	620	00	06	12					
	621	00	03	16					
	638	00	07	20					
	639	00	00	32					
	640	00	10	80					
	641	00	08	28					
	642	00	02	44					
	643	00	00	64					

[नंदा प्र-31015/49/93-ओ. प्र-1]

कुलवीप सिंह, प्रवर सचिव

New Delhi, the 27th October, 1993

S.O. 2342.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 702, dated the 29th February, 1992 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum ;

And whereas copies of the Gazette notification has been made available to the public on the 26th March, 1992 ;

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government ;

And whereas the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired.

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the rights of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest, free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited;

Schedule

Tehsil : Bahrar District : Alwar State : Rajasthan

Name of Village	Khasra No.	Area		
		Hec-tare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Sasedi	401	00	05	04
	722	00	06	84
	937	00	04	14
	968	00	09	90
	1041	00	00	36
Gunti	2083	00	13	68
Kali Pahadi	25	00	04	32
Kalyanpura	491	00	01	17
Jainpu was	884	00	04	32
Nagla Rundh	53	00	41	04
Kolila Rabad	293	00	02	88
	121	00	01	02
	122	00	05	76
	123	00	09	00
Kankar	127	00	03	10
	579	00	05	10
	929	00	08	28
	1116	00	00	80
Shimla	59	00	02	40
	60	00	07	92
	61	00	11	52
	65	00	43	56
	70	00	02	60
	71	00	20	16
	75	00	12	40
	193	00	12	24
	194	00	04	50
	195	00	03	06
	196	00	00	72

1	2	3	4	5
Shimla (Contd.)	266	00	10	26
	270	00	00	98
	271	00	07	88
	272	00	07	92
	273	00	00	50
	275	00	00	80
	276	00	00	24
	278	00	04	78
	279	00	06	24
	281	00	04	48
	282	00	04	48
	290	00	11	28
	291	00	01	40
	299	00	00	08
	301	00	06	04
	302	00	09	00
	305	00	13	50
	70/432	00	16	75
	271/461	00	03	60
Belni	254	00	00	96
	255	00	01	98
	257	00	18	90
	260	00	05	08
	261	00	12	96
	268	00	27	00
	270	00	15	12
	281	00	21	06
	282	00	00	78
	284	00	11	16
	285	00	05	94
	328	00	18	00
	330	00	18	90
	343	00	06	12
	344	00	12	96
	345	00	12	06
	484	00	12	96
	487	00	14	04
	344/577	00	02	02
Kolila Sanga	231	00	00	72
	232	00	12	10
	233	00	07	20
	237	00	21	92
	238	00	03	08
	239	00	10	80
	240	00	00	90
	248	00	17	10
	251	00	02	80
	252	00	39	06
	253	00	00	96
	272	00	11	16
	275	00	11	16
	276	00	10	80
	282	00	05	22
	292	00	11	16
	293	00	00	80
	465	00	06	12
	466	00	08	28
	467	00	01	44
	468	00	10	26
	522	00	05	04
	523	00	02	70
	527	00	08	82
	528	00	10	26
	530	00	01	44

1	2	3	4	5
Kolila Sanga (Contd.)	562	00	00	18
	563	00	05	04
	564	00	09	54
	565	00	02	34
	613	00	05	58
	615	00	11	52
	616	00	02	16
	620	00	06	12
	621	00	03	16
	638	00	07	20
	639	00	00	32
	640	00	10	80
	641	00	08	28
	642	00	02	44
	643	00	00	64
	663	00	00	36
	664	00	15	12
	665	00	01	00
	674	00	00	60
	675	00	15	84
	677	00	01	00
	678	00	06	48
	292/775	00	00	80
	292/776	00	04	32
Talwad Sarbiland Momanpur	222	00	01	08
	223	00	03	94
	224	00	06	84
	225	00	06	84
	226	00	05	04
	227	00	06	12
	228	00	04	86
	229	00	00	84
	234	00	07	20
	237	00	11	20
	238	00	12	48
	241	00	02	24
	242	00	00	96
	254	00	05	04
	255	00	02	88
	256	00	02	88
	271	00	09	72
	272	00	06	84
	273	00	12	24
	1377	00	08	82
	1378	00	09	00
	1396	00	11	88
	1397	00	22	86
	1403	00	17	82
	1423	00	15	12
	1425	00	15	30
	1427	00	04	00
	1428	00	06	88
	1429	00	10	00
	1431	00	03	90
	1432	00	14	40
	4134	00	01	08
	1435	00	02	88
	1396/1946	00	09	18
	1432/1977	00	00	32

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th October, 1993

S.O. 2343.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 1134, dated the 29th May, 1993 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) at page 1576, in the third line of first paragraph for "S.O. 43" read "S.O. 47".

[No. R-31015/34/93-OR-I]

KULDIP SINGH, Under Secy.

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1993

का.भा. 2344 —केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे हमने इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.भा. 3185, 43 और 45 तारीख 16 दिसम्बर, 1991, हिस्सा पाठ द्वारा जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) के क्रमशः पृष्ठ संख्या 4980 से 4982, 71 से 75 और 80 से 82 पर प्रकाशित हुई थी, यह घोषणा की थी कि पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि राजपत्र में उक्त अधिसूचना संख्या का.भा. 1124, 1127 और 1129 तारीख 28 अप्रैल, 1993, पृष्ठ संख्या 1572 से 1574 पर प्रकाशन में मुद्रण संबंधी कतिपय त्रुटियाँ पुनः हुई हैं ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रस्तुत शर्तों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची का निम्न प्रकार से संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. का.भा. 1124—पृष्ठ संख्या 1572 के बाहिने भाग में ऊपर से—

(i) पंक्ति 23 पर लिखें 'मोटी चिराई' के स्थान पर 'मोटी चिराई' पढ़ें।

2. का.भा. 1127—पृष्ठ संख्या 1573 के बायें भाग में ऊपर से—

(i) पंक्ति 4 पर लिखें '70' के स्थान पर '75' पढ़ें।

(ii) पंक्ति 5 पर लिखें '9 जनवरी, 1997' के स्थान पर '4 जनवरी, 1992' पढ़ें।

(iii) पंक्ति 6 पर लिखें '48' के स्थान पर '43' पढ़ें।

(iv) पंक्ति 7 पर लिखें '1 दिसम्बर 199' के स्थान पर '16 दिसम्बर 1991' पढ़ें।

3. का.भा. 1127—पृष्ठ संख्या 1573 के बाहिने भाग में ऊपर से—

(i) पंक्ति 9 पर लिखें '77' के स्थान पर '72' पढ़ें।

(ii) पंक्ति 11 पर लिखें '78' के स्थान पर '73' पढ़ें।

(iii) पंक्ति 12 पर लिखें 'रप गलवासना' के स्थान पर 'पर गलवासना' पढ़ें।

(iv) पंक्ति 14 पर लिखें '78' के स्थान पर '73' पढ़ें।

(v) पंक्ति 16 पर लिखें '79' के स्थान पर '74' पढ़ें।

(vi) पंक्ति 18 पर लिखें '79' के स्थान पर '74' पढ़ें।

(vii) पंक्ति 19 पर लिखें 'आलीपुर' के स्थान पर 'बालीपुर' और 'बलीपुर' के स्थान पर 'बलीपुर' पढ़ें।

(viii) पंक्ति 21 पर लिखें '79' के स्थान पर '74' पढ़ें।

[No. R-31015/49/93-O.R.I.]

KULDIP SINGH, Under Secy.

(9) पंक्ति 22 पर लिखे '2295' के स्थान पर '224/5' पढ़ें।

(10) पंक्ति 21 पर लिखे 'सब' के स्थान पर 'सब' पढ़ें।

4. का.भा. 1129-पृष्ठ संख्या 1574 के दाहिने भाग में पंक्ति 1 पर लिखे 'मीमागर' के स्थान पर 'मीमागर' पढ़ें।

यह और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेदन देती है कि उक्त भूमि के उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बावजूद, सभी बिल्लिंगों से मुक्त होकर, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

[संख्या-भार-31015/34/93 ओ.आर.-1]

कुलदीप सिंह, सचिव

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1993

का.भा. 2345.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में ग्राम माहुल (चेम्बूर), मुम्बई से ग्राम कैरा, जिला रायगढ़ तक नेप्था तक के परिवहन के प्रयोजनार्थ गमनागमन प्रवाह के लिए पाइपलाइन सी.पी.पी.एल. लिमिटेड द्वारा, जिसे पहले चेम्बूर पतालगांगा पाइपलाइन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, बिछाई जाएं:

और केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाइपलाइन बिछाई जाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि इस अधिभूत में उपायय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने प्राथम्य की घोषणा करती है;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितवश कोई व्यक्ति उस तारीख से, जिससे भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता का उपलब्ध करा दी जाती हैं, 21 दिन के भीतर, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन या भूमि में पाइपलाइन बिछाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में श्री एस.एस. देशमुख, सहाय प्राधिकारी, सी.पी.पी.एल. लिमिटेड, न्यू पनवेल (विशाल), संभर सं. 2, प्लॉट सं. 5, ग्राउण्ड फ्लोर, जिला रायगढ़-410206 को कर सकेगा।

अनुसूची

सहस्र-खालापूर	जिला-रायगढ़	राज्य-महाराष्ट्र			
ग्राम का नाम	सर्वेय / गट/खण्ड	हिस्सा सं.	क्षेत्र	हैक्टर	घर
1	2	3	4	5	6
सलेगाव	8	6 भाग	00	02	25
	8	2 भाग	00	03	00
	8	1 भाग	00	02	90
	7	6 भाग	00	01	15

[फा.सं. भार-31015/9/91-ओ.आर.-II]

कुलदीप सिंह, सचिव

New Delhi, the 28th October, 1993

S.O. 2345.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Naphtha from Village Mahul (Chembur), Bombay to Village Kaira, District Raigad in the State of Maharashtra, pipelines for on-wards and return stream by the CPPL Limited, formerly known as Chembur Patalganga Pipelines Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire for right of user in the lands described in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may within 21 days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri S. S. Deshmuch, Competent Authority, CPPL Limited, New Panvel (CIDCO), Sector No. 2, Plot No. 5, Ground Floor, District Raigad-410206;—

SCHEDULE

Tehsil : Khalapur	District : Raigad		State : Maharashtra		
Name of Village	S.No./ Gat. No.	Hissa No.	Area Hectare	Ac	Centiare
1	2	3	4	5	6
Telegaon	8	6 part	00	02	25
	8	2 part	00	03	00
	8	1 part	00	02	90
	7	6 part	00	01	15

[F.No. R-31015/9/91-OR-II]

KULDIP SINGH, Under Secy.

का.भा. 2346.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में ग्राम माहुल (चेम्बूर), मुम्बई से ग्राम कैरा, जिला रायगढ़ तक नेप्था के परिवहन के प्रयोजनार्थ गमनागमन प्रवाह के लिए पाइपलाइन सी.पी.पी.एल. लिमिटेड द्वारा, जिसे पहले चेम्बूर पतालगांगा पाइपलाइन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, बिछाई जाएं।

और केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाइपलाइन बिछाई जाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि इस अधिभूत में उपायय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने प्राथम्य की घोषणा करती है;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में द्वितीय कोई व्यक्ति उस तारीख, से, जिसके भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, 21 दिन के भीतर, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन या भूमि में पाइपलाइन बिछाने के संबंध में प्राचीन विहित रूप में श्री एस. एम. देशमुख, सक्षम प्राधिकारी, सी.पी.सी.एल. लिमिटेड, न्यू पनवेल (निर्वाह) सेक्टर प्लॉट सं. 5, ग्राउंड फ्लोर, जिला रायगड-410206 को कर सकेगा।

अनुसूची

तहसील—पनवेल		जिला—रायगड		राज्य—महाराष्ट्र	
ग्राम का नाम	सर्वे सं./ गट संख्यांक	हिस्सा	क्षेत्र	हैक्टर	घा. सेंटीघा.र
1	2	3	4	5	6
आजीवली	62	1	00	02	50

[फा. सं. आर-31015/1/93-ओ आर-II]

कुलदीप सिंह, अध. सचिव

New Delhi, the 28th October, 1993

S.O. 2346.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport Naphtha from Village Mahul (Chembur), Bombay to Village Kaira, District Raigad in the State of Maharashtra, pipelines for onward and return stream should be laid by the CPPL Limited formerly known as Chember Patalganga Pipelines Limited.

And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the lands described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may within 21 days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri S. S. Deshmukh, Competent Authority, CPPL Limited, New Panvel (CIDCO) Sector No. 2, Plot No. 5, Ground Floor, District Raigad 410206 :—

SCHEDULE

Tehsil—Panvel		District—Raigad		State—Maharashtra	
Name of village.	S.No./ Gat No.	Hissa	Area.		
			Hectare	Are	Cent.
1	2	3	4	5	6
Ajlvali	62	1	00	02	50

[F.No. R-31015/1/93-OR-II]

KULDIP SINGH, Under Secy

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1993

का. आ. 2347.—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3109 तारीख 17 नवंबर, 1990 द्वारा नेपाल पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 17 नवंबर, 1990 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को आती रिपोर्टें दे दी हैं;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सभी विल्लंगनों से मुक्त सी.पी.पी. एल. लिमिटेड में निहित होगा :—

अनुसूची

तहसील—कुर्ला	जिला—मुंबई उपनगर जिला			राज्य—महाराष्ट्र		
ग्राम का नाम	सर्वे सं. 1 गट सं.	हिस्सा सं.	सी.टी.एस. सं.	क्षेत्र		
				हेक्टेयर	आरे	सेंटेयर
1	2	3	4	5	6	7
आणिक	63	0 भाग	265 भाग	00	01	35
	12	25 भाग	263 भाग	00	01	90
	12	25 भाग	263 भाग	00	01	90
	64	0 भाग	261 भाग	00	03	00
	12	25 भाग	263 भाग	00	00	90
	74	0 भाग	260 भाग	00	00	25
	12	25 भाग	263 भाग	00	00	90
सड़क		भाग	263 भाग	00	00	06
	64	0 भाग	261 भाग	00	00	08
	64	0 भाग	263 भाग	00	00	09
	64	0 भाग	315 भाग	00	00	27
	64	0 भाग	313 भाग	00	02	20
				00	12	90

[फा. सं. आर—31015/1/91—ओ.आर. II]

कुलदीप सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 29th October, 1993

S.O. 2347.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, No. S.O. 3109, dated the 17th November 1990, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Pipelines for the transport of Naphtha|Petroleum Products;

And whereas the copies of the said Gazette Notification were made available to the public on the 17th day of November, 1990;

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government:

And whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Gov-

ernment hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest in the CPPL Limited free from all encumbrances;

SCHEDULE

Tehsil : Kurla District : Bombay Suburban District				State : Maharashtra		
Name of Village	S.No./ Gat No.	Hisasa No.	CTs No.	Area		
				Hect.	Acre	Cnet.
1	2	3	4	5	6	7
Anik	63	0 part	265 part	00	01	35
	12	25 part	263 part	00	01	90
	12	25 part	263 part	00	01	90
	64	0 part	261 part	00	03	00
	12	25 part	263 part	00	00	90
	74	0 part	260 part	00	00	25
	12	25 part	263 part	00	00	90
	Road		263 part	00	00	06
	64	0 part	161 part	00	00	08
	64	0 part	263 part	00	00	09
	64	0 part	315 part	00	00	27
	64	0 part	313 part	00	02	20
				00	12	90

[F. No. R-31015/1/91-O.R. II]

KULDIP SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1993

का.धा. 2348:—केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संभालय की अधिसूचना सं. का.धा. 3093 तारीख 17 नवम्बर, 1990 द्वारा नैफ्था के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने प्राणय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 17 नवम्बर, 1990 को उपलब्ध कर दी गई थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केंद्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का निश्चय किया है;

अतः, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और यह और कि केंद्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेदन देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केंद्रीय सरकार में निहित होने की वजह से सभी बिस्तरों से मुक्त सी.पी.पो.एल. लिमिटेड में निहित होना:—

अनुसूची

तहसील—पानवेल जिला—रायगढ़ राज्य—महाराष्ट्र

ग्राम का नाम	खंड/अंश संख्यांक	हिस्सा सं.	क्षेत्र		
			हेक्टर	भार	सेंटीभर
1	2	3	4	5	6
शेदुंग	114	भाग 2(1)	00	03	90

[का.सं. भार-31015/7/91-ओ भार-I]]

कुलदीप सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 29th October, 1993

S.O. 2348.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, No. S.O. 3093 dated the 17th November, 1990 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of Naptha;

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 17th day of November, 1990.

2401 GI/93—5.

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest in the CPPL Limited free from all encumbrances :

SCHEDULE

Tehsil—Panvel District—Raigad State—Maharashtra

Name of village	Survey/ No.	Hissa No.	Area		
			Hect.	Acre	Cent.
1	2	3	4	5	6
Shedung	114	2(1) part	00	03	90

[F.No. R-31015/7/91-OR-II]

KULDIP SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1993

का.धा. 2349:—केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संभालय की अधिसूचना सं. का.धा. 3086 तारीख 17 नवम्बर 1990 द्वारा नैफ्था की परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के अपने प्राणय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 17 नवम्बर, 1990 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का निश्चय किया है;

अतः, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और यह और कि केंद्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केंद्रीय सरकार में निहित होने की बजाए, सभी विलक्षणों से मुक्त सी.पी.पी.एल. लिमिटेड में निहित होगा:—

अनुसूची

तहसील—खालापूर		जिला—रायगड		राज्य—महाराष्ट्र	
ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्यांक	हिस्सा सं.	क्षेत्र		
			हेक्टर	घार	सेंटीघर
1	2	3	4	5	6
पानशील	98	0 भाग	00	00	90
	111	0 भाग	00	03	00

[फा.सं. भार-31015/3/91-ओ भार-II]

कुलदीप सिंह, भवर सचिव

New Delhi, the 29th October, 1993

S.O. 2349.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, No. S.O. 3086 dated the 17th November, 1990, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of Naptha;

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 17th day of November, 1990,

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands instead of vesting in the Central Government, vest in the CPPL Limited free from all encumbrances ;

SCHEDULE

Tehsil : Khalapur District : Raigad State : Maharashtra

Name of Village	S.No./ Gat No.	Hissa No.	Area		
			Hec.	Are	Cent.
1	2	3	4	5	6
Panshil	98	0 part	00	00	90
	111	0 part	00	03	00

[F. No. R-31015/3/91-OR-II]

KULDIP SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1993

का.भा. 1350:—केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत के राजपत्र, भाग 2 खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 15 जून, 1991 में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.भा. 1704, तारीख 15 जून, 1991 द्वारा यह घोषणा की थी कि उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का पाइपलाइन बिछाने के लिए अर्जन किया जाए;

अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार 15 जून, 1991 से केंद्रीय सरकार में निहित होने की बजाए सभी विलक्षणों से मुक्त सी.पी.पी.एल. लिमिटेड में निहित होगा।

[सं० भार.31015/11/91-ओ भार-II]

कुलदीप सिंह, भवर सचिव

New Delhi, the 29th October, 1993

S.O. 2350.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 1704, dated the 15th June, 1991, issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), published in the Gazette of India Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 15th June, 1991, the Central Government declared that the right of user in lands specified in the Schedule appended to that notification should be acquired for laying the pipelines;

Now in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government directs that the right of user in the lands specified in the Schedule annexed to the said notification instead of vesting in the Central Government vest in the CPPL Limited free from all encumbrances with effect from the 15th day of June, 1991.

[No. R-31015/11/91-OR-II]

KULDIP SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1993

का.भा. 2351:—केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक-हित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में ग्राम पाहुल (चैम्बूर), मुम्बई से ग्राम कैरा जिला रायगढ़ तक नेफ्था के परिवहन के प्रयोजनार्थ गमनागमन प्रवाह के लिए पाइपलाइन सी.पी.पी.एल लिमिटेड द्वारा, जिसे पहले चैम्बूर पातालगंगा पाइपलाइन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था बिछाई जाए;

और केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाइपलाइनें बिछाई जाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची के वर्णित भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने भाष्य की घोषणा करती है ;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, 21 दिन तक के भीतर,

उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन या भूमि में पाइपलाइन बिछाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में श्री एस.एस. देशमुख, सक्षम प्राधिकारी, सी.पी.पी.एल. लिमिटेड न्यू पनवेल (सिडको) सैक्टर सं. 2 प्लॉट सं. 5 ग्रांड फ्लोर, जिला रायगढ़-410206 को कर सकेगा।

अनुसूची

तहसील—पनवेल		जिला—रायगढ़		राज्य—महाराष्ट्र	
ग्राम का नाम	गट संख्यांक सर्वे सं.	हिस्सा सं.	क्षेत्र	हेक्टर	आर. सेंटीमीटर
1	2	3	4	5	6
शिलोत्तर रायचुर	45	14 भाग	00	01	75

[फा.सं. आर-31015/10/91-ओ आर-II]

कुलदीप सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 29th October, 1993

S.O. 2351.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Naphtha from Village Mahul (Chembur), Bombay to Village Kaira, District Raigad in the State of Maharashtra, pipelines for onwads and return stream by the CPPL Limited, formerly known as Chembur Patalganga Pipelines Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire for right of user in the lands described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may within 21 days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri S. S. Deshmukh, Competent Authority, CPPL Limited, New Panvel (CIDCO), Sector No. 2, Plot No. 5, Ground Floor, District Raigad (Maharashtra)—410206;—

SCHEDULE

Tehsil : Panvel District : Raigad State : Maharashtra

Name of Village	Gat No. S.No.	Hissa No.	Hectare	Area Aerea Centia	
1	2	3	4	5	6
Shilottar Raichur	45	14 part	00	01	75

[F.No. R-31015/10/91-OR-II]

KULDIP SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1993

का.भा. 2352:—केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1963 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.भा. 3102 तारीख 17 नवम्बर, 1990 द्वारा नैफ्था के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 17 नवम्बर, 1990 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केंद्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और यह और कि केंद्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेदन देती कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केंद्रीय सरकार में निहित होने की वजह से सभी विवादों से मुक्त सी.पी.पी.एल. लिमिटेड में निहित होगा:—

अनुसूची

तहसील—पनवेल		जिला—रायगढ़		राज्य—महाराष्ट्र	
ग्राम का नाम	सर्वेक्षण/ गट संख्यांक	हिस्सा सं.	क्षेत्र	हेक्टर	आर. सेंटीमीटर
1	2	3	4	5	6
ग्राम—शिलोत्तर रायचुर	42	5 भाग	00	01	50

[फा.सं. आर-31015/10/91-ओ आर-II]

कुलदीप सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 29th October, 1993

S.O. 2352.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, No. S.O. 3102, dated the 17th November, 1990, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of Naphtha;

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 17th day of November, 1990;

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government ;

And whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest in the CPPL Limited free from all encumbrances ;

SCHEDULE

Tehsil : Panvel District : Raigad State : Maharashtra

Name of Village	S.No./ Gat No.	Hissa No.	Hectare Arc	Area Centare	
1	2	3	4	5	6
Shil-ottar Raicur	42	5 part	00	01	40

[F.No. R-31015/10/93OR-II]
KULDIP SINGH, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1993

का. आ. 2353.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों और सक्षम बनाने वाले अन्य सभी प्रावधानों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्वारा, दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवास सम्पदा का प्रबन्ध एवं निपटान) विनियम, 1968 के अन्तर्गत निम्नित सम्पत्तियों के निपटान की पद्धति, एवं शर्तों का निर्णय लेने की अपनी सभी शक्तियां उपाध्यक्ष को सौंपता है।

[सं. एफ. 25(39)/91/इम्पल./डी.डी.ए.]
रणबीर सिंह, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 13th October, 1993

S.O. 2353.—In exercise of the powers conferred upon it by and sub-section (1) of Section 52 of the Delhi Development Act 1957 and all other enabling provisions, Delhi Development Authority hereby delegates, to its Vice-Chairman, all its powers to decide the manner, terms and conditions of disposal of built-up properties, under Delhi Development Authority (Management and Disposal of Housing Estates) Regulations 1968.

[No. F. 25(39)/91/Impl/DDA]
RANBIR SINGH, Secy

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1993

का.आ. 2354.—केन्द्रीय सरकार का, दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय (डिवीजनल) विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जाना की सूचना के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लॉक, आई. एन. ए., नई दिल्ली को इस सूचना के जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने/सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता भी दे।

संशोधन :

1. "खामपुर गांव की राजस्व सम्पदा में, पूर्व में वर्तमान नाला सं. 6 से, पश्चिम में जी.टी. करनाल रोड से, और उत्तर तथा दक्षिण में हरित पट्टी से घिरे 10 हेक्टेयर (25 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "ग्रामीण" उपयोग से "उपयोगिता" (मलजल शोधन संयंत्र) में बदलने का प्रस्ताव है।"

2. बूढ़पुर गांव और बीजापुर गांव के निकट, दक्षिण में बवाना एस्केप से, उत्तर में हरित पट्टी से, पश्चिम में जी.टी. करनाल रोड से और पूर्व में नहारी मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से घिरे लगभग 40 हेक्टेयर (100 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "ग्रामीण उपयोग" से "उपयोगिता" (मलजल शोधन संयंत्र) में बदलने का प्रस्ताव है।"

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिये उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छोटी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली में उक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य-दिवसों को उपलब्ध रहेगा।

[सं. एफ. 3(52)/91-एम.पी.]

रणबीर सिंह, सचिव

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 29th October, 1993

S.O. 2354.—The following modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan/Zonal (divisional) development Plan for Delhi, are hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modifications may send the objections/suggestions in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, I.N.A., New Delhi, within a period of thirty days from the date of issue of this notice. The person making the objection/suggestion should also give his name and address.

MODIFICATIONS :

(i) "The land use of an area, measuring 10 ha. (25 acres) bounded by existing drain No. 6 in the East, G.T. Karnal Road in the West and green belt in the North and South, in the revenue estate of village Khampur is proposed to be changed from 'rural use' to 'utility' (Sewage Treatment Plant)".

(ii) "The land use of an area, measuring 40 ha. (100 acres) near village Budhpur and village Bijapur, bounded by Bawana escape in the South, green belt in the North, G.T. Karnal Road in the West and green belt Nahari, major distributory in the East, is proposed to be changed from 'rural use' to 'utility' (Sewage Treatment Plant)".

2. The plan indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Deputy Director, Master Plan Section, 6th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi, on all working days within the period referred above.

[No. F. 3(52)/91-MP]

RANBIR SINGH, Secy.

Delhi Development Authority

श्रम मन्त्रालय

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1993

का.आ. 2355—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंडियन एयर लाईन्स के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-11012/7/90-आई आर (विधि)]

के.वी.बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 7th October, 1993

S.O. 2355.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management to M/s. Indian Airlines and their workmen, which was received by the Central Government on 6th October, 1993.

[No. L-11012/7/90-IR (Misc.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 79/90

In the matter of dispute between :

Shri Roop Ram S/o Shri Nathi Ram through Indian Airlines workmen Association Regd.

Versus

M/s. Indian Airlines through the Manager Personnel Services, Thapar House, New Delhi.

APPEARANCES:

None—for the workman.

Shri M. J. Paul—for the Management

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-11012/7/90-IR(Misc.) dated 8/90 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Indian Airlines, New Delhi in imposing punishment of reduction of basic pay by 3 stages with cumulative effect on Shri Roop Ram, Master Technician vide their order dated 5th May, 1986 and subsequently restoring two increments in July, 1987 was justified. If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The workman in this case had died and the parties had been taking time for settlement but none have been appearing on behalf of the workman or his representative for the last six dates. It appears that parties are not interested in getting the dispute adjudicated upon after the death of the workman. I, therefore, pass a no dispute award in this case.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1993

का.आ. 2356—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंडियन एयर लाईन्स के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-11012/8/90-आई आर (विधि)]

के.वी.बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th October, 1993

S.O. 2356.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Indian Airlines and their workmen, which was received by the Central Government on 6-10-93.

[No. L-11012/8/90-IR (Misc.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA; PRESIDING OFFICER; CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL; NEW DELHI

I.D. No. 80/90

In the matter of dispute between

Shri Roop Ram through the Regional Secretary, Indian Airlines Workmen Association, C5B/150, Janakpuri Delhi-58.

Versus

The Manager Personnel, Indian Airlines, Thapar House, Janpath, New Delhi.

APPEARANCES :

None for the workman.

Shri M. J. Paul for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-11012/8/90-IR(Misc) dated 8/90 has refer-

red the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Indian Airlines, New Delhi in imposing punishment of reduction of basic pay by one stage in the time scale with cumulative effect on Shri Roop Ram, Master Technician vide their order dated 4/11-10-88 was justified. If not, to what relief the workman is entitled?"

The workman in this case had died and the parties had been taking time for settlement but none have been appearing on behalf of the workman or his representative for the last six dates. It appears that parties are not interested in getting the dispute adjudicated upon after the death of the workman. I, therefore, pass a no dispute award in this case.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

1st October, 1993.

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 1993

का.आ. 2357—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्वय में केन्द्रीय सरकार एन डी आर आई कर्नाल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण चंडीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[मं० एल-42012/25/87-डी.-2(बी)पार्ट]

के.वी.बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 12th October, 1993

S.O. 2357.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure. in the industrial dispute between the employers in relation to the management of N.D.R.I., Karnal and their workmen, which was received by the Central Government on 7-10-93.

[No. L-42012/25/87-D.II(B)(Pt.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I.D. 71/88

Om Parkash Vs. N.D.R.I.

For the workman : Shri P. S. Arora.

For the management : Shri D. S. Virk.

AWARD

Central Government vide Gazette Notification No. L-42012/25/87-D.II (B) dated 30th September, 1988 issued U/s. 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the NDRI, Karnal in terminating the services of Shri Om Parkash son of Shri Pokar Dass, general labour w.e.f. 1-8-1986 is legal and justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled and from what date?"

2. Case of the petitioner in the statement of claim that he was employed as daily paid labour (unskilled) w.e.f. 11-8-81 through employment exchange. He has shown to have worked in three spells from 11-8-1981 to 8-4-1982, 22-9-1982 to

14-5-1983 and 21-12-1985 to 31-7-1986. He alleges that on 31-7-1986 he was not allowed to resume his duty and alleges violation of Section 25-F of the I.D. Act. He also claims violation of Section 25-H of the I.D. Act at the hands of the management having employed Chandreshwar Parshad Yadav and Tulsi Dass after his termination and sought reinstatement with full back wages w.e.f. 1-3-1986.

3. The management resisted the claim of the petitioner. In written statement preliminary objection has been taken that provisions of Section 25-F and Section 25-H are not applicable, petitioner being employed for a specific purpose and for specific period. On merits the management has taken the stand that the petitioner never worked continuously for 700 days and not entitled to compensation and reinstatement being provisions of Section 25-F do not apply. It is further claimed that there is no question of any vacancy or post held by him however the petitioner was employed only for specific period. Other workmen were employed for purely different purposes and that too for specific period. Thus there is no violation of Section 25-G and Section 25-H of the I.D. Act, 1947. Unfair labour practice was also denied and sought the dismissal of the present claim.

4. The petitioner in support of his case produced himself as WW1. He filed his affidavit Ex. W1. He also relied on certificates P.x. W2 and W3 and W4. The management had produced MW1 Capt. Mehar Singh, Admn. Officer. He filed his affidavit Ex. M1. Respective parties closed their case.

5. I have heard both the parties, gone through the evidence and record.

6. The petitioner had worked with the respdt. management on three spells. The dispute relevant in the present reference is the last spell in which the petitioner had admittedly worked from 21-12-1985 to 31-7-1986. He has not worked at all in the year 1984. However between the period 21-12-85 to 31-7-1986 he does not complete 240 days which is the mandatory requirement in order to attract the provisions of Section 25-H of the I.D. Act, 1947. The petitioner had only completed 223 days and not 240 days during the said course of last employment. Therefore, the termination is certainly not in violation of Section 25-F of the I.D. Act for having not paid retrenchment compensation and pay in lieu of notice.

7. Counsel appearing on behalf of the petitioner also alleges violation of Section 25-H of the I.D. Act, 1947 having employed Chandreshwar, Parshad Yadav and Tulsi Ram after his termination and alleges unfair labour practice at the hands of the respdt. management. This plea is again meritless legally as well as factually. The term of reference in the present case relates to termination of services of the petitioner w.e.f. 1-8-1986. The alleged violation of Section 25-H is the event subsequent to the termination of the petitioner which is not the issue in the present reference. The Tribunal is required to confine its adjudication to the points of dispute specified in the order of reference and the matter incidental to them. The issue of unfair labour practice or discrimination or employment given to some persons subsequently is not a matter referred to the Tribunal for adjudication, nor can it be said to be in any way connected with the right of re-instatement claimed by the petitioner. The fairness of subsequent appointment of some workmen is a matter quite irrelevant for judging the validity of the earlier termination of the petitioner—it is an entirely separate and independent question. The ratio of Firestone Tyre and Rubber Co. of India (P) Ltd. Vs. their workmen reported in 1981 (Vol. 59) F.J.R. page 249 is followed.

8. Coming to the facts of the present case, no doubt that the management has nowhere denied that they have not employed fresh hands after the termination of the petitioner but their stand is that the fresh requisitions to the employment exchange were sent and whosoever is sponsored by the employment exchange is generally taken which the workman could not refute having no such suggestion put to the management's witness that the subsequent employment of said three persons namely Chandreshwar Parshad Yadav and Tulsi Dass were not through employment exchange. The grievance of the petitioner of unfair labour practice has to be specific for which he is heavily burdened to prove by way of cogent evidence that he has been terminated from the post only in order to accommodate fresh hands and conduct of the employer falls within the mischief of unfair labour practice

as defined in clause (ra) of Section 2 of I.D. Act, 1947. He has failed to prove that the post against which he was working continued after his termination. He has miserably failed to prove that the appointment of said three persons subsequently was done immediately by the respdt. management. In these circumstances it can not be said that the post against which the petitioner was working was continued after the termination of his services and filled immediately thereafter by appointing said three persons attracting unfair labour practice.

9. Hence nothing survive in the proceedings initiated by the petitioner and he is not entitled to reinstatement and back wages. Reference is returned to the Ministry. Chandigarh, 30-9-1993.

ARVIND KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 1993

का.आ. 2358—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्वय में केन्द्रीय सरकार टेलीकाम वारंगल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अन्वय में निनिदष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40012/21/91-आई आर (डी यू) पार्ट]

के.वी.बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 12th October, 1993

S.O. 2358.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecom Warangal and their workmen, which, was received by the Central Government on 11-10-93.

[No. L-40012/21/91-IR (DU) (Pt.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT

HYDERABAD

PRESENT :

Sri Y. Venkatachalam, M.A., B.L., Industrial Tribunal-I.

Dated, 27th day of September, 1993

Industrial Dispute No. 49 of 1991

BETWEEN

Md. Sarwar, S/o Md. Yakub Ali,

about 20 years, Casual Mazdoor, under the Respondent. herein.

.. Petitioner.

AND

The Sub-Divisional Officer, Phone, Warangal-506 007.

.. Respondent

APPEARANCES :

M/s. C. Suryanarayana & P. Bhaskar, Advocates—for the Petitioner.

M/s. M. Panduranga Rao & B. G. Ravinder Reddy, Advocates—for the Respondent.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-40012/21/91-IR(DU) dt. 3-10-1991 referred the

following dispute under Section 10(1)(d) & (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the Management of M/s. Telecom, Warangal (A.P.) and their workmen to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of M/s. Telecom, Warangal (A.P.) represented by their Sub-Divisional Officer, in terminating the service of Shri Md. Sarwar without complying with the provisions of the Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 is justified? If not, to what relief, the workman concerned is entitled?"

2. The brief facts of the claim statement filed by the Petitioner-workman read as follows : The Petitioner's claim for reinstatement in service is based on the fact that the Respondent herein recruited and employed the Petitioner as Casual Mazdoor for 304 days during the period from 1-2-1986 to 31-5-1987 but retrenched thereafter on the ground that he was recruited after 30-3-1985 contrary to the orders of the Director-General, P&T New Delhi prohibiting any fresh recruitment and employment of Casual Mazdoors. The Petitioner was not given notice nor paid wages as per the mandatory provisions of Section 25-F of the I.D. Act. His subsequent employment during short spells only indicates, in view of the provisions of Section 25-B of the I.D. Act the Petitioner was in continuous service till 31-3-1989 and effectively retrenched from service w.e.f. 1-4-1989 again in gross violation of the mandatory provisions of the said Section 25-F. In Daily rated Casual Labour in P&T V. Union of India & others (AIR 1987 SC 2342) the Supreme Court directed that a Scheme be worked out by the P&T Departments to absorb, as far as possible, the Casual labourers who have rendered one year continuous service (with at least 240 days service to their credit). Thus, the Supreme Court conferred on the workmen the right of absorption in the regular establishment of the Departments because the Casual workman no longer remains "Casual" after rendering one year continuous service. Notwithstanding the aforesaid direction of the Supreme Court, the petitioner was retrenched from service w.e.f. 1-4-1989 on the fallacious ground that he was recruited after 30-3-1985, the date on which the Director-General imposed ban on fresh recruitment/employment of Casual Mazdoors. The retrenchment was without complying with the mandatory provisions of Section 25-F of the I.D. Act. In a similar case, when some Casual Mazdoors of Delhi Telephones, recruited after 30-3-1985 were retrenched the Principal Bench of the Hon'ble Central Administrative Tribunal at New Delhi declared that in view of the above mentioned judgement of the Supreme Court (AIR 1987 S.C. page 2342) the executive orders of the D.G. dt. 30-3-1985 are no more valid and that even Casual Mazdoors recruited/employed after that date are entitled to absorption in the regular establishment on a regular basis on rendering one year continuous service, vide its judgement dt. 4-5-1988 in OA No. 529/88 between Sunder Lal & Others Union of India & Others (unreported). In fact, in a subsequent decision dt. 17-4-1990 in WP (C) No. 1280/89 and batch of cases between Ramgopal and Others and Union of India & Others etc. (not reported) the Hon'ble Supreme Court upheld the above mentioned judgement dt. 4-5-1988 and declared that no distinction can be drawn between Mazdoors recruited before 30-3-1985 and those that are recruited on or after that date and that all those who have rendered one year continuous service are entitled to the benefits of the judgement in AIR 1987 SC 2342. The Petitioner submits that after absorbing several mazdoors, the Telecom Department issued orders No. 269-10/89-STN, dt. 7-11-1989 to grant temporary status to those who could not be absorbed in the regular establishment for want of vacancies. It is thus an incidence of continuous one year service as Casual labourers in the Telecom Department to be conferred with temporary status pending their absorption in the regular establishment of the Department which takes place according to their turn in the seniority list of casual mazdoors of a recruitment unit and for preparing the seniority list the Director General issued separate orders. The petitioner therefore prays that this Hon'ble Tribunal may be pleased to hold and declare that his retrenchment is illegal, null and void and consequently to direct the respondents herein to reinstate him in service with full back wages, continuity of service, protection of his seniority and all other benefits which are consequential and/or

temporary status pending his absorption in the regular establishment to make the Award accordingly.

3. The brief facts of the counter filed by the Respondent Management read as follows : It is submitted that the reference itself is illegal for the reason that the services of the petitioner were never terminated as he was only working on casual basis and the casual mazdoors were offered work as and when the same is available. It is submitted that the Department engages casual mazdoors as and when temporary works are taken up for laying ground cables and construction of overhead alignments are taken up. As soon as the work is over, the employment of the casual mazdoor comes to an end. Likewise, if another work is taken up, and the casual mazdoor comes forward for employment, he will again be engaged till the work lasts. It is submitted that in the case of casual mazdoors, work is not continuous and their engagement depends upon the availability of work. The petitioner was engaged as a casual mazdoor in the subdivision on the following dates viz. 23 days in February, 1986, 29 days in March, 1986, 30 days in April, 1986, 18 days in May, 1986, 28 days in November, 1986 and 31 days in December 1986. He also worked 29 days in January, 1987, 23 days in February, 1987, 24 days in March, 1987, 28 days in July, 1987, 21 days in August, 1988 and 31 days in September, 1988. Again he worked 25 days in February, 1989 and 19 days in March 1989. It is submitted that there is a procedure for recruitment of regular employees in the departments, and therefore, the claim of the petitioner that he should be made a permanent employee is not maintainable. As already submitted, the services of casual mazdoors come to an end as and when the work is completed. Till fresh works are taken up, he will have to remain idle. Such disengagement is automatic in the case of casual mazdoors. It is submitted that the petitioner is not entitled to continue in service mechanically as a casual labour. It is submitted that there is no termination of the services of the petitioner, and therefore, the dispute itself is not maintainable. It is therefore, prayed that this Hon'ble may be pleased to pass an Award holding that the petitioner is not entitled to any relief.

4. The point for adjudication is whether the action of the Respondent-Bank in terminating the service of Md. Sarwar without complying with the provisions of the Section 25-F of the I.D. Act is justified ?

5. W.W1 was examined on behalf of the Petitioner and marked Exs. W1 to W5 on its side. M.W1 was examined on behalf of the Respondent and no documents were marked on its side.

6. W.W1 is Md. Sarwar. He deposed that he joined the Department as Casual Mazdoor on 1-2-1986 and he continued till 1-4-1989. From 1-2-1986 to 1-6-1987 he worked for a total of 304 days. Ex. W1 is the working days particulars. At the time of termination on 1-4-1989 he was neither given any notice nor was paid notice period wages in lieu of the notice. No reason was given for his termination. No written orders were served on him, stating that he was removed from service. He used to go to SDO, Tel. and requested for work. He was not given any work. The only reason that was given by the SDO, Tel. is that those who are recruited after 30-3-1985 are being terminated. Some of his juniors are still continued in the department. He therefore prays this Hon'ble Tribunal to hold and declare that his termination is illegal, null and void and consequently direct the Respondent to reinstate into service with all attendant benefits.

7. M.W1 is A. Shedrak. He deposed that he is deposing on the basis of the records. The Petitioner was engaged as casual mazdoor. Casual mazdoors are engaged to temporary works like digging trenches, erecting of pole laying cables etc. It is not a regular and continuous work. The casual mazdoors are engaged for specific works and when that work was completed, they would be disengaged. The petitioner was initially engaged in February, 1986. He was engaged lastly in the month of March, 1989. Between this period, there were gaps for the engagement of the petitioner and he did not work during the months of June, 1986 to October, 1986 and June, 1987 to June, 1988 and from

October, 1988 to January 1989. As there was no work immediately after March, 1989, the petitioner could not be engaged as casual mazdoors.

8. The argument of the Petitioner is that the Respondent recruited and employed the Petitioner as Casual Mazdoor for 304 days during the period from 1-2-1986 to 1-6-1987 but retrenched thereafter on the ground that he was recruited after 30-3-1985 contrary to the orders of the Director General, P&T New Delhi prohibiting any fresh recruitment and employment of Casual Mazdoors. On the other the contention of the Respondent is that there is a procedure laid down for recruitment of regular employees in the Department, and therefore the claim of the petitioner that he should be made a permanent employee is not maintainable. The services of casual mazdoor comes to an end as and when the work is completed. Till fresh works are taken up, he will have to remain idle. Such disengagement will not amount to termination and such disengagement is automatic in the case of casual mazdoors.

9. In this case this Tribunal has to see whether the order passed terminating the services of the Petitioner under is proper or not ? Of course there is no dispute with regard to the recruitment of the petitioner and the number of days the petitioner worked under the Respondent i.e. Sub-Divisional Officer, Warangal. Now the contention of the Petitioner is that the Order of the Director General, P&T, Department, New Delhi Lr. No. 269/130/78-STN dt. 1-10-1984 was in existence prior to the date of recruitment of the petitioner i.e. the Petitioner was recruited on 1-2-1986. The Respondent now cannot assert that the recruitment of the petitioner was in contravention of the above order dt. 1-10-1984. When the Petitioner has served the Respondent for a long time wherein the Petitioner has put in 304 days of service. Now the Respondent cannot say that the order of recruitment was erroneous. On the other hand, it is also seen that very many persons have been employed and still continuing in service even though the Order of the Director General, P&T New Delhi is in existence. This clearly shows that the retrenchment of the petitioner from service with effect from 1-4-1989 was based on wrong application of the Standing Orders and contrary to the principles of justice and arbitrary and discriminatory. Since the Petitioner-workmen has put in more than 304 days attendance is eligible to acquire temporary status and is eligible for all the benefits and privileges like regular employees. In support of the case of the petitioner he has cited judgements of the Supreme Court and Central Administrative Tribunal.

10. In the judgement of the Central Administrative Tribunal Principal Bench, New Delhi in the case of SUNDARLAL & ORS. v. UNION OF INDIA, the Hon'ble Tribunal directed the Respondent that those labourer employed after 1-4-1985 and who had put in one year service are entitled for absorption, their services could not be terminated and further directed for reinstatement forthwith. There is another judgement of the Supreme Court in W.P. No. 373 and 302 of 1986 dt. 27-10-1987, wherein the Supreme Court observed that these Casual labourer render the same kind of service as regular labour. The directive principles of State Policy as contained in article 38 provides to minimise the inequalities in income. The Supreme Court further directed the authorities to incorporate a scheme on National basis for absorbing casual labour who have been continuously working for more than one year in the Post & Telegraph Departments. The Respondent has not rebutted to the decisions of the Supreme Court and Central Administrative Tribunal, in this Tribunal.

11. So taking into consideration of all the facts and circumstances of the case, I am clearly of the view that the Orders of the Sub-Divisional Warangal in terminating the services of the Petitioner workman is ill-motivated and without any valid grounds and is liable to be quashed as arbitrary and illegal.

12. In the result, the action of the Management of M/s. Telecom, Warangal (AP) represented by their Sub-Divisional Officer, in terminating the services of Sri Md. Sarwar without complying with the provisions of the Section 25-F of the Industrial Dispute Act, 1947 is not justified. The said workman is entitled to be reinstated into service with full back wages and all other attendant benefits.

Award passed accordingly.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 27th day of September, 1993.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I.

Appendix of Evidence

Witnesses Examined for the
Petitioner/Workman :

W.W-1—Md. Sarwar

Witnesses Examined for the

Respondent/Management :

M.WI.—A. Shedrav.

Documents marked for the Petitioner/Workman :

Ex. W1.—Xerox copy of the Working days particulars of the Petitioner/Workman.

Ex. W2 29-5-89.—Xerox copy of Complaint given to RLC (Central) Hyderabad with regard to illegal retrenchment of the petitioner from service given by the Petitioner/Workman.

Ex. W3.—Xerox copy of parawise remarks submitted by the SDO Phones Warangal with reference to the Dispute raised by the Petitioner/Workman.

Ex. W4 25-8-89.—Xerox copy of the rejoinder submitted by the Representative for the Petitioner-Workman to the above parawise remarks.

Ex. W5.—Xerox copy of the Failure report with regard to the dispute of the Petitioner/Workman.

Documents marked for the Respondent :

NIL

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 1993

का.आ. 2359—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेंट्रल रेलवे के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण नं. 1, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं.एल-41012/88/91-आई आर (डी यू)-पार्टे]

के.वी.बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 15th October, 1993

S.O. 2359.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Railway and their workmen, which was received by the Central Government on 13-10-93.

[No. L-41012/88/91-IR (DU)-(Pt.)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL NO. I, BOMBAY

PRESENT :

Justice Shri R. G. Sindhakar, Presiding Officer.
2401 GJ/91-6,

Reference No. CGIT-17 of 1992

PARTIES :

Central Railway, Bombay.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Management : Shri P. R. Pai, Advocate.

For the Workmen : Shri Y. R. Singh, Advocate.

INDUSTRY : Railways

STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 24th day of September, 1993

AWARD

By order dated 24th March, 1992, Government of India, Ministry of Labour, made following reference to this Tribunal :

"Whether the action of the management of Central Railway, Bombay V.T. Bombay in ordering compulsory retirement of Central Railway from service with effect from 1st May, 1984 ? If not, what relief he is entitled to ?"

And

"Whether the management of Central Railway, Bombay justified in not settling the retiral/terminal dues due to Shri D. P. Wagh and his demand as per Annexure-I after retiring him compulsorily from service with effect from 1-5-1984 ? If not, what relief he is entitled to ?"

2. Shri Wagh was served chargesheet dated 15th June, 1981, alleging demand and acceptance of bribe of Rs. 90 for the issue of a fitness medical certificate. He denied the charge and the grievance is that chargesheet was vague and the date, time and place of the alleged demand and acceptance of bribe was not mentioned. It was further stated that he was not the authority to issue such fitness certificate and the Enquiry Officer failed to consider that the charge was vague. The petitioner's dismissal, therefore, was challenged by an appeal. However, the appellate authority set aside the order of dismissal from service and converted it into the compulsory retirement with effect from 1st May, 1984. The workman Shri Wagh challenges the order of dismissal.

3. The management filed written statement. It contended that the reference was not proper and valid and has been made without application of mind. It is contended with the enquiry was fair and proper and is according to statutory rules. Opportunity was given to him defend himself. It is then contended that the charge levelled against him was clear. The case is that the action is justified.

4. It so happen that during the pendency of this reference Shri D. P. Wagh unfortunately expired on 9th August, 1993. The certificate has been issued by Chief Medical Superintendent, Central Railway Hospital, Kalyan. In view of the death of the workman, prayer for setting aside the order of compulsory retirement, compensation and relief of retirement would not survive.

5. It is, however, found that the later part of the reference is dealing with his payments, not settling retiral/terminal dues of Sri Wagh and his demands as per Annexure I. Unfortunately there is no Annexure with the reference. However, if that be the position, I am sure, the management of Central Railway will settle retiral/terminal dues and pay them to his heirs, entitled. In the absence of Annexure also it is not possible to adjudication upon the same. The award according.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 1993

का.आ. 2360—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, डायरेक्टर टेलेकाम (सेंट्रल एरिया) लखनऊ के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-5-1990 को प्राप्त हुआ था।

[एल-40012/120/89-डी-2 (बी) पार्ट]

के.वी.वी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 15th October, 1993

S.O. 2360.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Director Telecom (Central Area) Lucknow and their workman, which was received by the Central Government on 2-5-90.

[No. L-40012/120/89-D-II(B)(Pt.)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI ARJAN DEV PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 131 of 90

In the matter of dispute between :
Pardesi Lal C/o Sri S. B. Singh,
Divisional Secretary Bhartiya,
Telephone Karamchhari Sangh
Mahamagar, Lucknow.

AND

Director,
Doorsanchar (Central Area),
Seth Bhawan Lila Cinema
Ke Pichhe, Nawal Kishore Road,
Lucknow.

AWARD

1. The Central Government Ministry of Labour vide its notification number L-40012/120/89-D.2(B) dated 2-5-90 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

Whether the Director Telecom (Central Area) Lucknow was justified interminating the services of Sri Pardesi Prasad w.e.f. 29-2-88 ? If not, what relief the workman was entitled to ?

2. In this case 22-3-93 was the date fixed for the cross examination of the workman, on the said date neither the workman nor any body on his behalf appeared. It happened to be the second day for the cross examination of the workman. Admittedly the workman had worked continuously as a daily rated casual labour from June 1986 to February 1988. The contention of the workman is that his services were terminated in violation of the provisions of section 25F of the I.D. Act.

3. In defence it has been pleaded by the management that the services of the workman were terminated w.e.f. 1-3-88 by giving him one month's notice dated 1-2-88, in accordance with the instructions contained in circular memo dated 1-1-84 issued by the Government of India, Ministry of Communication, New Delhi. It is further pleaded by the management that the workman declined to receive compensation when offered. Since admittedly he had worked continuously for one year within the meaning of section 25B of the Act before the termination of his services, his services could be terminated validly only after complying with the provisions of section 25F of the Act. Act said above according to the

management the services of the workman were terminated by giving him one month's notice and retrenchment compensation. However that is no evidence in this regard from the side of the management, but in view of what has been held by me in my award dated 6-11-92, given in I.D. No. 88/88, Bholu Nath Agarwal Versus G. M. Telecom Kanpur on the basis of judgement dated September 11, 1990 of C.A.T. Allahabad in T.A. No. 1239 of 87 Achhaiber Lal Versus Union of India, no relief can be granted to the workman. In the said order dated 11-9-90, C.A.T. Allahabad has held that Telecom Department is not 'Industry'. Further on O.A. No. 552 of 1989 Union of India and others Versus Shyam Sunder Lal and other C.A.T. Allahabad in its order dated 26-2-91 has held that C.A.T. Allahabad has jurisdiction to entertain an application under section 19 of the Central Administrative Tribunal's Act, 1985 against the order passed by an Industrial Tribunal/Labour Court under section 33C(2) of the Act.

4. Hence, what has been held by C.A.T. Allahabad, it is held that Telecom Department is not an Industry. This being so the reference made by the Ministry of Labour, Government of India, is misconceived. It is decided accordingly.

ARJAN DEV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1993

का.आ. 2361—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार में भारत कोकिंग कोल लिमि. की किरसगढ़ कोलियरी के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 2) धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-20012/169/90-आई आर (कोल-I)]

हरीश गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th October, 1993

S.O. 2361.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal (No. II) Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kessurgarh Colliery of M/s. B.C.C.L. and their workmen which was received by the Central Government on 8-10-1993.

[No. L-20012/169/90-IR (C-I)]

HARISH GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) DHANBAD

PRESENT :

Shri B. Ram. Presiding Officer.

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

Reference No. 85 of 1991

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kessurgarh Colliery of M/s. B.C.C.L. and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen—Shri D. Mukherjee, Secretary Bihar Colliery Kamgar Union.

On behalf of the employers—Shri B. Joshi, Advocate.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 23rd September, 1993

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/169/90-I.R. (Coal-I), dated, the 14th March, 1991.

"Whether the Management of Kessargarh Colliery in Block II Area of M/s. B.C.C. Ltd. is justified in dismissing Shri Ramji Munda Mines from service w.e.f. 30-8-75 ? If not, what relief the workman is entitled ?"

2. As per terms of reference we are to consider the justification of the action of the management of Kessargarh Colliery of Block No. II Area of M/s. BCCL in dismissing Shri Ramji Munda, Miner from service with effect from 30-8-75. At the very outset it may be mentioned that the same reference was disposed off vide Ref. No. 37/76 by the Central Government Industrial Tribunal No. 3 at Dhanbad on 17-4-78. The photo copy of the award has been filed which forms part of the record and it may be read as Ext. M-12. It may also be noted herethat simultaneously a criminal proceeding was also initiated against the concerned workman arising out of same set of facts and circumstances.

3. The action of the management under the award No. 37/76 was held to be justified and so the aggrieved concerned workman had gone before the Hon'ble High Court, Ranchi Bench, Ranchi in the Writ jurisdiction against the Award. The Hon'ble Court was pleased to dismiss the Writ application vide order dated 10-7-89 in the CWJC No. 24/1983 (R). The photo copy of the judgement is Ext. M-11. While the matter was pending before the Hon'ble High Court the concerned workman was acquitted from the criminal charges vide criminal appeal No. 105/78 dated 13-5-86. The photo copy of the judgement has been marked Ext. M-1. On the basis of that judgement of acquittal the learned counsel for the applicant before the Hon'ble High Court had pleaded that the petitioner who was dismissed during the pendency of the Criminal case had since been acquitted by the Criminal Court and so on the basis of subsequent event the petitioner was entitled to take necessary steps for getting a reference made by the appropriate Government. In the light of this submission the Hon'ble Court had observed that if a dispute is raised as contended by Mrs. Pal, the same shall be disposed off by the appropriate Government on its own merit. In this way the present reference has been made on the basis of subsequent event which is the judgement of acquittal by the Criminal Court. Thus in the instant reference the matter for consideration will be very short and limited.

4. We have to examine as to whether the action of the management can be declared unjustified and the concerned workman be reinstated with full back wages on the ground of his acquittal from the Criminal Court ?

5. Before dealing with the legal aspect of the matter on this point it may be relevant to state a few facts of the case in short. The concerned workman was issued chargesheet on 24-8-73 with the allegation that on 21-8-73 at about 0.30 A.M. he along with one Batulal B.P. Hard Coke Stacker seriously assaulted one Shri Sakaldip Gope while he was returning home after his duty hour. He was further charged that after the incident he started absenting from duty without any permission or notice. Thus he was charged for serious misconduct under clause 17(n) and (r) of the Standing Order applicable to the Establishment of Kessargarh Colliery of M/s. BCCL. The concerned workman had replied to the chargesheet but he did not attend the domestic enquiry. Most probably he was in the custody at that time in criminal case. Naturally he did not attend the domestic enquiry and so it was held ex parte against him. The enquiry officer concluded enquiry and submitted report heading the concerned workman guilty of the misconduct. The report was approved by the authority and accordingly he was dismissed from the service. The concerned workman raised industrial dispute vide Ref. 37/76 which was disposed off by the Tribunal No. 3, Dhanbad. The learned Tribunal held

the action of the management to be justified and it was against the said award the concerned workman had invoked the Writ Jurisdiction of the Hon'ble High Court.

6. The learned counsel for the concerned workman submitted that the chargesheet (Ext. M-2) was defective and misleading for it did not disclose the place of occurrence. It was urged that the management cannot take any disciplinary action against its workman for any incident occurring beyond the premises of the Colliery. It was contended that the employer has got no extra territorial jurisdiction. Reliance was also placed upon a decision reported in Indian Factories and Labour Report, December, 1983 at page 508 (M/s. Glaxo Laboratories (I) Ltd. vrs. The Presiding Officer). Their Lordship of the Hon'ble Supreme Court were pleased to hold that the management is not the custodian of the general law and order situation nor the Guru or mentor of his workman for their well regulated cultural advancement. If the power to regulate the behaviour of the workman outside the duty hours and at any place wherever they may be was conferred upon the employer, contract of service may be reduced to contract of slavery. The employer has both power and jurisdiction to regulate the behaviour of workmen within the premises of the establishment, or for peacefully carrying the industrial activity in the vicinity of the establishment." By placing this fact it was contended that the alleged occurrence of assault had taken place beyond the premises of the Colliery of the management and the management was not justified to take any departmental proceeding against the concerned workman. The contention of the learned counsel could have been very much appreciated but in my humble opinion the stage is over and the chapter has already been closed when the learned Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad in Ref. No. 37/76 held the ex parte domestic enquiry to be fair proper and in accordance with the principles of natural justice. By the said award the learned Tribunal also held that there were materials on the record to prove the misconduct of the concerned workman and according the action of the management was held to be justified in dismissing the concerned workman from service. This Court at this stage cannot reconsider the domestic enquiry or the finding arrived at by the Enquiry Officer because the matter has already proceeded too far. The learned Tribunal passed an Award which has already been confirmed by the Hon'ble High Court. As regards non-mentioning of the place of occurrence in the chargesheet issued against the concerned workman, I find that this aspect of the matter was canvassed even in Ref. No. 37/76.

7. The learned counsel for the concerned workman further urged that during the pendency of the Criminal Trial the management should have withheld the departmental proceeding and awaited the result of the criminal trial. Reliance was placed upon a decision reported in LLJ 1988—Vol. II at page 407. Their Lordship of the Hon'ble Supreme Court were placed to hold as follows :—

"It is not possible to settle the law in a straight-jacket formula as judicial opinion appeared to be conflicted on the question as to whether the disciplinary action had to be stayed till the criminal case was over. It would be a hazardous step to lay down law in a straight-jacket formula as that would create a greater hardship in some cases."

Mostly the Hon'ble Court further observed that where criminal action and departmental proceedings are based on same set of facts, disciplinary proceeding should be stayed pending Criminal trial. In appropriate case disciplinary proceeding can await disposal of criminal case. Further reliance was placed upon the authority reported in LLJ 1992 Vol. I at page 226. That was a case in which an employee of Port Trust of Bombay was charged in criminal case for alleged theft of bail bearings valued at Rs. 1800. After trial the employee was acquitted by the Criminal Court and he was allowed to join his duty but disciplinary action was taken and a domestic enquiry was initiated after three years and four months. He was found guilty and compulsorily retired. Their Lordships held as follows :—

"When once an employee is honourably acquitted and completely exonerated at the criminal trial normally the Port Trust could not be started and proceeded with the departmental enquiry unless there was a strong and sound reasons to do so."

Lastly reliance was placed upon a decision reported in L.L.J. 1993 at page 168 wherein their Lordships of the Hon'ble Supreme Court held as follows :—

"The departmental enquiry should be stayed till the trial before the Chief Metropolitan Magistrate, Madras is completed. If the respondents so choose, they can proceed with the enquiry after the judgement is rendered by trial Court, whether any appeal is filed or not against the decision of the trial Court."

8. From the above authorities it is well established that the result of the Criminal Court should be awaited. It should also be honourably respected just for the sake of maintaining and upholding the dignity of the Court. If the order and the judgements of the Courts are ignored the people in general will start losing faith and confidence in the instance which is one of the back bone of democracy. But here at this stage it may be pertinent to mention that this Tribunal cannot reconsider the domestic enquiry afresh for the award has already been passed in Ref. No. 37/76 and the same has been upheld held by the Hon'ble High Court. The learned counsel for the concerned workmen has not cited any authority to show that the judgement of the Criminal Court which is the subsequent event in this case can be considered at any stage of the award already passed. The award-Ext. M-12 justifying the action of the management was confirmed by the Hon'ble High Court. In the circumstances, I think the concerned workman cannot get any relief specially when the Writ petition has already been dismissed.

This is my Award.

B. RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 1993

का.प्र. 2362 — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एफ सी आई के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/1/एफ90-आईआर(सी-II)]

राजालाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th October, 1993

S.O. 2362.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workmen, which was received by the Central Government on 7-10-1993.

[No. L-22012/1/F/90-IR (C-II)]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 16/92

In the matter of dispute :

BETWEEN

Shri Mohd. Ayub,
through Mahamantry,
Food Corporation of India Executive
Employees Union (North Zone)
2337, Dharampura, Ghe Pee Wara front
Chawri Bazar, Delhi-110006.

Versus

Anchal Prabhandhak (North)
Food Corporation of India,
Fourth Floor, Ansal Bhawan,
Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi-110001.

APPEARANCES :

Shri Vinod Kumar with the workman.

Shri Daya Kishan Deputy Manager, Admn. alongwith
Shri V. K. Malhotra.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-22012/1/F/90-IR. (C-II) dated 24-2-92 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in debarring their workman Shri Mohd. Ayub, Assistant Grade I (Depot), from promotion vide order dated 28/29-3-88 particularly when he was not relieved to join new place of posting, is justified? If not, to what relief the concerned workmen is entitled to?"

2. The dispute between the parties was amicably settled and on the application of the parties the case was taken up. Parties filed settlement Ex. M-1. It was duly signed by both the parties. In view of this settlement Ex. M-1 shall form part of this award. Parties are directed to be bound by the terms of the settlement and shall bear their own costs of this dispute.

Dated : 16th September, 1993.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT.
INDUSTRIAL TRIBUNAL, ANSAL BHAVAN,
NEW DELHI

I. D. No. 16/1992

Date of Hearing
26-10-1993,

Shri Mohd. Ayub through
the General Secretary,
FCI Executive Employees Union (NZ) Workman
Vs.

The Zonal Manager (North),
Food Corporation of India,
Ansal Bhavan, Kasturba
Gandhi Marg, New Delhi. Management

Subject.—Application for consent award between the parties in the above noted matter.

Respected Sir,

Most respectfully sheweth :—

1. That the Government of India, Ministry of Labour vide their Order No. L-22012/1/F/90-IR (C-II), dated the 24th February, 1992 referred the following dispute to this Hon'ble Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the Management of Food Corporation of India in debarring their workman Shri Mohd. Ayub, Assistant Grade-I (Depot) from promotion vide order dated 28/29-3-1988 particularly when he was not relieved to join the New place of Posting is justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled to?"

2. The FCI Executive Employees Union, North Zone which has raised the dispute leading to the order of adjudication by Government of India Ministry of Labour discussed the issue for amicable settlement of the dispute on 12-1-1993.

3. That after detailed discussions, it has been agreed by both the parties to settle the dispute on the following terms and conditions :—

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BANGALORE

Dated (this 29th day of September, 1993)

Present :

Sri M. B. Vishwanath, B.Sc., B.L., Presiding Officer.

Central Reference No. 17/93

I party
The Gen. Secretary,
F.C.I.E.U.,
No. 1, Mission Road,
Bangalore-27.
(By Sri S. Raju, Adv.)

v/s.

II party
The Regional Manager,
Food Corporation of India,
No. 10, Mission Road,
Bangalore.
(By Sri Y.K.N. Sharma, Adv.)

AWARD

In this reference made by the Hon'ble Central Govt. by its order No. L-22012/345/F/92-IR (C. II) Dt. 23-2-93 under Sec. 10(2A) (1) (d) of I.D. Act the point for adjudication as per schedule to reference is :—

"Whether the action on the part of the management of Food Corporation of India in denying promotion of Asst. Grade-I as well as denial of fixing correct position in the seniority list of Asst. Grade-II in respect of workman Sh. D. Krishna Murthy is justified ? If not to what relief the workman are entitled to?"

2. In the claim statement the I party workman D. Krishna Murthy has contended that he joined service on 31-1-71. The II party published the seniority list of Asst. Grade-III on 22-8-73. In this list the I party workman's name is at Sl. No. 303. The names of other employees viz., N. Surya Rao, A.R. Mohan Rao, K.E. Mohana Sundaram and K. Saibabu are Sl. No. 305, 307, 314 and 316 respectively. The I party workmen and the others were promoted as Asst. Grade-II by common order dt. 7-5-76. The II party has published a provisional list of Assts. Grade-II on 30-9-77. In this list while Mohana Sundaram, A. R. Mohana Rao and Surya Rao though junior to I party workman in Asst. Grade-III, have been placed wrongly above I party workman. This seniority list is wrong. The Seniority list of Asst. Grade-II published by II party as on 30-9-77 is to be recast, and the I party workman D. Krishna Murthy should be placed above Mohana Sundaram, Sai Babu, Surya Rao and Mohana Rao. Secondly I party has to be promoted as Asst. Grade-I from the date of the aforesaid persons who are promoted as Asst. Grade-I.

3. In the counter statement the II party has justified its action.

4. Neither party has adduced evidence. Both parties relied on the admitted documents and argued the matter.

5. In the seniority list of Asst. Grade-III as on 31-12-71 the I party workman D. Krishna Murthy is shown at Sl. No. 303, whereas the other four persons are below the I party workman. This seniority list is correct, obviously based on the date each party joined service.

6. By common order dt. 7-5-76 the I party workman and the other four persons in question were promoted as Asst. Grade-II. In this promotion order the I party is at Sl. No. 16 and the other 4 persons are at Sl. Nos. 20, 24, 27 and 29 respectively.

7. From the admitted facts stated above it is abundantly clear that the I party workman is senior to A. R. Mohana Rao, Surya Rao, Mohana Sundaram and Sai Babu. Therefore I held that seniority list of Asst. Grade-II as on 31-12-82 showing the I party workman at Sl. No. 49 below Mohana Sundaram, K. Surya Rao and Mohana Rao is clearly wrong.

(a) That the Zonal Offices (North) Order dated 28/29-3-1988 debarring Shri Mohd. Ayub bearing No. E.I/2(4)/87/NZ.

from promotion for a period of one year is to be withdrawn and his order of promotion bearing No. E-1/2(4)/87-NZ, dated 29-12-88 is to be restored with modified place of posting to New Delhi.

(b) That neither the union nor the workman will claim arrears of pay at any state of time on account of notional empanelment and notional Pay fixation upto the date of joining on promotion. The notional pay, will, however, be admissible to him from the date of his joining at the place of posting.

(c) That the cost of the case will be borne by respective parties.

That the Hon'ble Tribunal may be pleased to decide the issue in the form of consent award.

Sd/-
WORKMAN
THROUGH
Sd/-
Sd/-

Sd/-
MANAGEMENT
Food Corporation of India
New Delhi
DAYA KRISHAN, Dy. Manager(ADMN)

Its authorised
representative
(VINOD KUMAR)
General Secretary,
FCI, Executive Employees
Union (NZ), New Delhi.

Its authorised
representative
(A. N. RAINA)

Dated : 16th September, 1993.

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 1993

का.आ. 2363—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एक सी आई के प्रबंधन से संयुक्त नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बेंगलूर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/345-एफ/92-आईआर(सी-2)]

राजलाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th October, 1993

S.O. 2363.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Bangalore as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workmen, which was received by the Central Government on 6-10-93.

[No. L-22012/345/F/92-IR.C-II]
RAJA LAL, Desk Officer

ORDER

It is hereby declared that I party workman D. Krishna Murthy is entitled for promotion as Asst. Grade-I w.e.f. the date Mohana Sundaram, K. Sai Babu were promoted and he shall be placed above A. Rama Mohana Rao and Shivarاما Sharma, Mohana Sundaram, K. Sai Babu and K. Surya Rao. This order is made taking into consideration the award in C.R. 18/93.

The II party shall grant all consequential reliefs to the I party workman. But he is not entitled to back wages in the promotional post. Reference accepted as stated herein. Submit to Government.

(Dictated to Stenographer, typed by him, corrected, signed by me on this 29th day of Sept., 1993).

M. B. VISHWANATH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 1993

का.आ. 2364:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस सी सी एल के प्रबंधन से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निहित औद्योगिक औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-10-93 को प्राप्त हुआ था।

13 या एन-22012/313/90-आईआर(सी-2)]

राजा लाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th October, 1993

S.Q. 2364.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S.C.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 5-10-93.

[No. L-22012/313/90-IR C-II]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri Y. Venkatachalam M.A., B.L., Industrial Tribunal-I.

Dated, 4th day of September, 1993

Industrial Dispute No. 17 of 1991

BETWEEN

The President, S.C.M.K. Sangh (BMS), P.O. Ramakrishnapur, Dist. Adilabad. ...Petitioner.

AND

The General Manager, M/s. S.C. Co. Ltd., P.O. Kalyan-khanl, Dist Adilabad ...Respondent.

APPEARANCES :

Sri R. N. Reddy, Counsel—for the Petitioner.

M/s. K. Srinivasa Murthy and G. Sudha, Counsels—for the Respondent.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-2012/313/90-IR(C.II), dated 12-6-1991 referred the following dispute under Section 10(1)(d) (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in rela-

tion to the Management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri and their workmen to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Management of M/s. S.C. Co. Ltd., Mandamarri, in dismissing Sri Joseph Victor, Driver, Kalyanikhanl w.e.f. 26-7-1978 from Company's services is justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

This reference is registered as Industrial Dispute No. 17 of 1971 and notices were given to both the parties.

2. The brief facts of the claim statement filed by the Petitioner-Union read as follows :

It is submitted that Sri Joseph Victor S/o Marian, the concerned workman in this dispute, was appointed in the year 1966 as General Mazdoor by the Respondent and later promoted as Driver in the year 1975. And that he went on leave from 4-6-1978 to 15-6-1978 and could not report for duty immediately after the completion of his leave due to his sickness. And that the Respondent struck off the name of Sri Victor from rolls of the Company as per the Company's Standing Order 11(C). Therefore he submitted a representation dated 20-12-1982 which did not solicit any reply. And that he approached the Singareni Collieries Workers Union and its office bearer Sri V.T. Abraham who raised an industrial dispute by letter dated 9-1-1984. Unfortunately Sri V. T. Abraham was murdered in the same year and the case of the workman suffered a set back. It is submitted that Sri Victor again approached the Company authorities. He filed representations dated 22-3-1986 and 9-5-1986 for which the Chief Personnel Officer of the Respondent Company was kind enough to reply by letter dated 28-5-1986 stating that his case was under consideration. The Chief Personnel Officer also wrote another letter dated 3-9-86 stating that the workman was interviewed on 26-6-84 for a temporary job of Driver, but he could not be appointed due to the calling of the strike by the Drivers, and no further reply was received by the workman. During the conciliation the management refused to take back the workman for duty on the plea that the claim was belated. But the Union submitted their views explaining the delay as stated above. It is submitted that the concerned workman was removed from service illegally by the Respondent without giving him an opportunity to explain in the reasons for his over stay after the leave expired and that no charge was levelled against the concerned workman for the absenteeism calling for the explanation from him. No enquiry was conducted on the charge. Thus the Respondent company violated the principles of natural justice. The Company's Standing Order 11(c) is illegal and unreasonable and ultra vires of the Constitution of India since it provides unreasonable powers to the Respondent to remove the permanent workman without any enquiry. It is submitted that the several Hon'ble High Courts and the Hon'ble Supreme Court of India in number of judgements held that the termination of service for any reason other than that the disciplinary action, termination by efflux of time in terms of agreement, loss of lien in terms of Standing Order and striking off name of a workman from rolls by the employers amounts to retrenchment under Section 2(uo) of the I.D. Act and the workmen are entitled for the benefit under Sec. 25-F of the I.D. Act. Admittedly in the case of Sri Victor no notice was given to him under Section 25F of the I.D. Act. It is submitted that the Respondent considered several cases of the persons whose name were struck off from the rolls of the Company and appointed them in the Company but failed to consider the case of Sri Victor. The Respondent was to keep the names of persons whose names were struck-off as per the Clause 11(C) of the Company's Standing Order in the Badli list as provided for in the same clause, but in the case of Sri Victor the respondent failed to maintain his name in the Badli list. For the above reasons it is prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to pass an award holding the action of the Respondent company in striking off the name of Sri Joseph Victor, Ex. Driver from rolls of the company in 26-7-1978 as illegal and unreasonable and in consequence direct the Respondent to reinstate Sri Joseph Victor Driver into service with all consequential benefits including full back wages or otherwise the concerned workman will be put to great hardship and irreparable loss and pass such other order or orders as this Hon'ble Tribunal deems just and necessary.

3. The brief facts of the counter filed by the Respondent Management reads as follows:—During the disputed period Sri Joseph Victor was working as Ambulance Driver for vehicle bearing No. API 1709 at Ramakrishnapur R. N. Dispensary and in normal course of his duties he had to take vehicle as per the need between Mandamarri Dispensary and Area Hospital, Bellampalli Sri Joseph Victor was on duty on 26-5-1978. While in official duty on that day he took the ambulance vehicle No. API 1709 and drove it in harsh and negligent manner and caused fatal accident to Sri Samala Gouriah Trammer, KK 2 Incline of the company. The public who have witnesses this accident became furious, set ablaze the ambulance, seized the dead-body of Gouriah, thus created law and order problem. He submitted a leave application on 4th June, 1978 requesting the Management to sanction leave from 4th June, 1978 to 15th June, 1978. For the period he requested, management has sanctioned leave. Even after expiry of the leave sanctioned, he did not turn up for duty nor had he asked for extension of leave, but just absented. As such, the Management was constrained to pass orders under Clause 11(C) of the Company's Standing Orders. The allegation that he submitted a representation on 28th December, 1982 is totally false. It is submitted that in the year 1984 the Drivers at Ramakrishnapur area issued a strike notice. So as to see that the entire work should not come to a stand-still, at that time to make alternative arrangements for mining work and transportation of coal etc., management interviewed several drivers for temporary posts. At that time the workman in dispute submitted an application and he was also interviewed on 26th June, 1984 for temporary job of driver. But he could not be appointed due to calling off of the strike by drivers. The allegation that the concerned workman was removed from service illegally by Company without giving any opportunity to explain reasons for his over-stay after the leave expired, is totally false. It may be noticed that the Petitioner Union and the other Union which alleged to have espoused his case are very active and raised several demands from 1978 to 1991 and also entered into settlements. It is submitted that no enquiry was conducted on the charge and that the Respondent company violated the principles of natural justice is not correct. It is not necessary to issue a notice to Sri Joseph Victor under Section 25-F of the I.D. Act. The Petitioner has misconstrued the legal position. It is true that the Company has considered several cases of similarly placed employees and considered them on merits those who have approached the management within one year. Sri Joseph Victor's case cannot be viewed sympathetically he alleged, as he failed to comply his obligations under a law, failed to report when accident occurred abandoned the vehicle, never bothered to find out what had happened to the vehicle. It is submitted that there are no merits in the petitioner's case, the workman in dispute is not entitled for award as prayed for, much less for reinstatement with all consequential benefits including full back wages; and the action of the management being justified, the claim petition filed by the petitioner may please be dismissed with costs. In view of the above mentioned facts, this Hon'ble Court may be pleased to dismiss the application.

4. W.W.1 was examined on behalf of the Petitioner Union and marked Exs. W1 to W12. On the other hand M.W1 and M.W2 were examined on behalf of the Respondent and marked Exs. M1 to M3.

5. The point for adjudications whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri in dismissing Sri Joseph Victor, Driver, Kalyanikhani w.e.f. 26th July, 1978 from Company's services is justified?

6. W.W1 is A. Joseph. He deposed that he is the concerned workman in the reference in this I.D. He applied for leave from 4th June, 1978 to 15th June, 1978 and the leave was sanctioned. He could not report to duty on the expiry of the sanctioned leave as he fell sick. One week thereafter he reported to duty and submitted a medical certificate from a private doctor. The Respondent did not accept his medical certificate and informed him that his name was struck out from the rolls under Clause 11(c) of certified Standing Orders of the Respondent. So he approached the Personnel Officer and the General Manager and represented his case and re-

quested them to reinstate him and they did not permit him to join duty. So he submitted a representation dated 1st February, 1986 to the General Manager of the Respondent requesting him to reinstate him into service. Again the Chief Personnel Officer wrote another letter dated 3rd September, 1986 to him stating that the drivers strike is called off and therefore he cannot be accommodated and the photostat copy of the said letter is Ex. W4. While he was driving the ambulance on 26th May, 1978 an accident took place near C. R. Club, Mandamarri. In the said accident one Mr. Shyamala Gouriah workman of K.K.2 Incline came on a cycle in a drunken state in the opposite direction and fell underneath the back wheel of the ambulance and died in the accident. So he went to the Mandamarri Police Station and gave a report about the accident. During the investigation it found that the accident was not occurred due to his fault and the case was referred treating the case as accidental as per final report submitted by the Inspector of Police, Mancherial and the final report was recorded treating the case as accidental and the F.I.R. was closed by the Judicial First Class Magistrate, Luxettipet. The xerox copy of the final report submitted by the Inspector of Police Mancherial under Section 173 Cr. P.C. in Crime No. 33 of 1978 of Mandamarri Police Station is Ex. W9. He prays the Tribunal to pass an award holding that the action of the Respondent in striking off his name from rolls of the Company on 26th July, 1978 as illegal and unreasonable and to direct the Respondent to reinstate him into service with full back wages and other consequential benefits. No domestic enquiry was conducted in this case against him. Though he tried to secure job elsewhere after he was removed from service, he could not secure any job till now.

7. M.W1 is B.I. Vijay Kumar. He deposed that he is working as Personnel Officer in Singareni Collieries Company Limited since 10 years. He is well acquainted with the facts of this case. The petitioner was appointed on 31st March, 1966. On 26th May, 1978 the Company ambulance driver by the petitioner was met with an accident. After the accident the petitioner responded that he has not given any information to the management. After the gap of one week, he applied for leave from 4th to 15th June, 1978 and that leave was sanctioned. On 16th June, 1978 the petitioner was supposed to attend duty but he has not turned for duty. After that the petitioner never reported for duty at any time. As the Petitioner lost his lien, he was removed from the service as per company's Standing Order 11(C). He was removed from service through their letter dated 27th June, 1978 with effect from 16th June, 1978. They have not received any representation from the Petitioner of that then H.M.S. and B.M.S. Unions representations. They have not received any representation from the petitioner on 20th December, 1982 as he mentioned in his claim statement. The workman is not entitled for any relief even as per the above agreement.

8. M.W2 is V. Datta Prasad Rao. He deposed that he knows the case of Joseph Victor who was employed as Driver at Dispensary Mandamarri as Ambulance Driver. On 26th May, 1978 accident took place while Joseph Victor was driving Ambulance. The Ambulance Van hit a cyclist and person died on the spot. Thereupon workers gathered there set ablaze the vehicle. He was not at the spot at that time. After that incident, Joseph Victor has not attended the duty. For one week he remained absent. He applied for leave. After expiry of the leave even after 10 days he has not attended the duty. So he was removed from the duty as per Standing Orders. No representation has come from any Union or employee Joseph Victor come from availing the benefit under Ex. M1. Item No. 9 Ex. M3 is 27th June, 1978 letter given to him intimating him to loose his lien under 11-C those employees who availed opportunity under settlement the list has been prepared and the employees were sent to the mine to be on the rolls as Badlies.

9. The claim of Joseph Victor is that he was dismissed from service from 27th June, 1978 (Ex. M3) without notice and enquiry and hence the same amounts to retrenchment under Section 2(oo) of the I.D. Act and the Respondent did not comply with the provisions of the Section 25-F of the I.D. Act and therefore he is entitled for reinstatement with back wages. He relies on 1984 Lab. I.C. 90 W.P. No. 704/90 1982 Lab. I.C. page 811 and 1985 L.I.C. 1733. He further relied on 1988 (II) LLJ 343 and 1986 Lab. I.C. 1203 with regard to laches. The Respondent opposed the claim of the Petitioner on the ground of laches saying the reference is about 12 years

later. They rely on 1964 (I) LLJ page 622. Further they argued that Joseph Victor was involved in an accident on 26th May, 1978 which resulted in a death of a person. Further the name of Joseph Victor was struck off from the rolls in terms of Standing Order No. 11(C) of the certified Standing Order.

10. The admitted facts of the case are (i) Joseph Victor was removed from the rolls from 27-6-1978 through Ex. M3 (ii) No notice was given or no enquiry was conducted before such removal, (iii) the Accident occurred on 26-5-1978 to the Ambulance which was driven by Joseph Victor. Striking of name of a workman from the rolls by any management without giving notice or conducting an enquiry is an action to be struck down by any Industrial Court. Before anything falls on anybody's neck he has to be informed that what for his neck is being cut. I am guided in this respect by the decision of our Hon'ble High Court in MOHD. ABDUL KHADER v. A. P. STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION reported in 1984 Lab. I.C. Page 90 in which case the regulation 39 of the A.P.S.R.T.C. Employees (Leave) Regulations 1963 was in question. And the said regulation is similar to that of Standing Order No. 11(c) of the Certified Standing Orders of the Singareni Collieries Company Limited. And that the said regulation was held bad and the Bench held that :

"We must hold that the termination of the services of the petitioner herein for overstay on expiry of the leave amounts to retrenchment and as admittedly neither the requirements of Section 25-F have been fulfilled by the Management nor any enquiry whatsoever was held to justify the action of the termination on the ground of misconduct, the impugned proceedings must be quashed."

In view of the above clear findings, I find that I need not look into any other decisions since the facts of the above case are very much similar to the case of the present dispute of the petitioner.

11. Further the Management opposes the claim mainly on the ground of laches relying on 1964 (II) LLJ page 622. Here again I find that I am guided by later decisions one of the Hon'ble Supreme Court 1988 (II) LLJ page 343 wherein the workman was denied backwages for the delay in approaching the Court. And the Hon'ble Karnataka High Court in 1986 Lab. I.C. 1203 held that instead of dismissing the petition consequential benefits are restricted for 3 years. Therefore I am of the clear view that the case of the petitioner shall not be rejected totally for the reason of delay. However the petitioner explains the delay through exhibits upto some extent and therefore the benefits can be restricted. Further the accident issue is solved by Ex. W12 wherein the investigation officer found that the accident was not due to negligence of Joseph Victor and the Judicial First Class Magistrate, Laxettipet closed the criminal proceedings. However it is not the case of the management also that Joseph Victor was dismissed from service due to the said accident. Therefore this issue has no relevancy to the industrial dispute. For the above reasons I have no hesitation to hold that the management is not justified in dismissing Joseph Victor on 26-7-1978 from service and in consequence direct the management to reinstate Joseph Victor as Driver.

12. In the result, the action of the Management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri, in dismissing Sri Joseph Victor, Driver, Kalyanikhan w.e.f. 26-7-1978 from Company's service is not justified. Sri Joseph Victor is entitled to be reinstated into service with full back wages and with all other attendant benefits.

Award passed accordingly.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 4th day of September, 1993.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I
Appendix of Evidence

Witnesses Examined on
behalf of the Petitioner/
Workman:

W. W1 A. Joseph

Witnesses Examined on
behalf of the Respondent/
Management:

M.W1 B.I. Vijay Kumar
M.W2 V. Datta Prasad.

Documents marked for the Petitioner:

- Ex. W1 9-1-84—Letter to intimate the Conciliation Proceedings Letter to ALC Mancherial by Vice President of the Union.
- Ex. W2 1-2-86—Letter given to the G.M. for re-appointment by the Petitioner-workman.
- Ex. W3 28-5-86—Reply by CPO to W2 (Photo-stat copy)
- Ex. W4 3-9-86—Another reply by C.P.O.
- Ex. W5 19-9-88—Representation before ALC(C) Mancherial by the Union.
- Ex. W6 15-2-91—Rejection of the reference by the Government of India.
- Ex. W7 27-3-91—Advocate's Note to the Secretary, Ministry of Labour.
- Ex. W8—Postal Acknowledgement to Ex. W7.
- Ex. W9—Xerox copy of Final Report submitted by the C.I. of Police Mancherial in Crime No. 33/78, U/Sec. 173 Cr. P.C.
- Ex. W10 Original of Ex. W3.
- Ex. W11—Original of Ex. W4.
- Ex. W12—Original of Ex. W9.

Documents marked for the Management:

- Ex. M1 29-1-89—Settlement xerox copy.
- Ex. M2—Xerox copy of Standing Orders.
- Ex. M3 27-6-78—Letter of intimation of losing the lean.

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 1993

का.आ. 2365—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एक सी आई के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बंगलोर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/341/एफ/93-आईआर(सी-2)]

राजालाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th October, 1993

S.O. 2365.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workmen, which was received by the Central Government on 6-10-1993

[No. L-22012/341/F/92-IR.C-II]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BANGALORE

Dated, this 29th day of September, 1993

PRESENT:

Sri M. B. Vishwanath, B.Sc., B.L., Presiding Officer.

Central Ref. No. 18/93

The General Secy.,
F.C.I. Employees Union,
No. 10, Mission Road,
Bangalore-27.

The Regional Manager,
Food Corporation of India,
No. 10, Mission Road,
Bangalore-27.

(By Sri Y.K.N. Sharma, Adv.)

AWARD

In this reference made by the Hon'ble Central Government by its Order No. L. 22012/341/F/92-IR(C.II) dt. 23-2-93 under Section 10(2A)(1)(d) of I.D. Act, the point for adjudication as per schedule to reference is:—

"Whether the action on the part of the management of Food Corporation of India in denying the promotion of Asstt. Grade-I as well as denial of fixing correct position in seniority list of Asstt. Grade II in respect of workmen Shri A. R. Mohana Rao and Shri J. K. Shivarama Sharma is justified? If not, to what relief the workmen are entitled to?"

2. The two I party workmen A. Ramamohana Rao (A. R. Mohana Rao) and Sri J. K. Shivarama Sharma have stated in their claim petition that though they are senior to K. E. Mohana Sundaram and K. Sai Babu they have been placed below these two persons in the seniority list of Asstt. Grade-II as on 30-9-77. They have stated they made representations that this seniority list was incorrect but the list has not been corrected. They have prayed that an award should be passed directing the II party to recast the seniority list of Asstt. Grade II and place them above K. E. Mohana Sundaram and K. Sai Babu and consequently promote them as Asstt. Grade I from the date Mohana Sundaram and Sai Babu were promoted.

3. In the counter statement it is contended by the II party that everything is in order and the seniority list published is perfectly alright. They have prayed that the reference should be rejected.

4. In the order sheet dated 30-7-93 it is stated that the point for consideration is covered by the schedule to reference and no separate issues are necessary.

5. Neither party has adduced evidence. Both the Learned Counsel argued on the basis of records produced.

6. I will refer to the documents produced and arrive at the conclusion.

7. The seniority list of Asstt. Grade III as on 31-12-71 shows that the Sl. No. of A. R. Mohana Rao is 307 and Shivarama Sharma is 311. This seniority list shows that Sl. No. of Mohana Sundaram is 314 and that of Sai Babu is 316. This seniority list of Asstts. Grade-III on 31-12-71 is based on the date of joining service as Asstt. Grade-III. This Seniority List shows that A. R. Mohana Rao joined the service on 10-2-71 and Shivarama Sharma joined service on 20-2-71, whereas Mohana Sundaram joined on 27-2-71 and Sai Babu joined service on 29-3-71.

8. The office order showing the promotion of Asstt. Grade-III as Asstt. Grade-II (Ministerial) is produced. This shows that all the four persons of Asstt. Grade-III in question have been promoted as Asstt. Grade-II. In this order of promotion A. R. Mohana Rao is at Sl. No. 20, Shivarama Sharma is at Sl. No. 24, whereas Mohana Sundaram is at Sl. No. 27 and Sai Babu is at Sl. No. 29.

9. From the facts stated above it is clear that A. R. Mohana Rao and J. K. Shivarama Sharma are senior to Mohana Sundaram and Sai Babu. In the seniority list of Asstt. Grade-II dated 31-12-82 A. R. Mohana Rao is shown at Sl. No. 47 and Shivarama Sharma is shown at Sl. No. 51, but Mohana Sundaram is shown at Sl. No. 23 and Sai Babu is shown at Sl. No. 26. Bearing in mind the date of joining service of the I party workmen and their seniority in the Asstt. Grade-III list the conclusion is inescapable that the seniority list of Asstt. Grade-II as on 31-12-87 is wrong and the I party workmen are entitled to come above Mohana Sundaram and Sai Babu.

2401 GI/93—7.

ORDER

It is hereby declared that the I party workmen A. R. Mohana Rao and Shivarama Sharma are entitled for promotion as Asstt. Grade-I w.e.f. the date K. E. Mohana Sundaram and K. Sai Babu were promoted as Asstt. Grade-I and both the workmen shall be placed above Mohana Sundaram and Sai Babu.

The II party management shall grant all the consequential reliefs to the I party workmen. But they are not entitled to back wages in the promotional post. Reference accepted as stated herein. Submit to Government.

(Dictated to Stenographer, typed by him, corrected, signed by me on this 29th day of September, 1993).

M. B. VISHWANATH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 1993

का.आ. 2365.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 11) की धारा 17 के अन्तर्गत में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन के संबंधित निजीकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अन्तर्गत में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/10/87-डी-II(ए)]

एल एस के राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 12th October, 1993

S.O. 2365.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 11-10-93.

[No. L-12012/10/87-D-II(A)]

S. S. K. RAO, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT
HYDERABAD

PRESENT :

Sri Y. Venkatachalam, M.A., B.L., Industrial Tribunal-I.

Dated 27th day of September, 1993

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 47 OF 1987

BETWEEN

The Workmen of State Bank of India,
represented by State Bank Employees'
Union (affiliated to AIBFA) Peddibhotla-
vari Street, VIJAYWADA-520 001. .. Petitioner

AND

The Management of State Bank of India,
Region III, Regional Office, Tirupathi,
Chitoor District. .. Respondent.

APPEARANCES :

M/s. D. S. R. Varma & C. Balajinarayana, Advocates
for the Petitioner-Workmen.

M/s. K. Srinivasa Murthy, G. Sudha, A. Visalakshmi,
Advocate for the Respondent-Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-12012/10/87-D.II(A), dt. 24-9-1987 referred the following dispute under Section 10(1)(d) & (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the Management of State Bank of India and their workmen to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action on the part of the Management of State Bank of India in relation to Region III, Tirupathi in serving notice of termination dated 9-10-86 on Sri M. Ramakrishna Rao, Messenger informing that his services will stand terminated with effect from 30-11-1986 is fair and justifiable ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

The reference is registered as Industrial Dispute No. 47 of 1987 and notices were served to both the parties.

The brief contents of the claim statement filed by the Petitioner read as follows :—Sri M. Ramakrishna Rao joined the Eluru Branch of the Respondent Bank as Godown Watchman on 1-1-1970. After he had put in more than 240 days continuous service, the Respondent Bank illegally and unjustifiably terminated his services. His case was taken up by the Petitioner Union and Sri Ramakrishna Rao was reinstated and posted as Messenger at Tirupathi Branch on 10th August, 1983. He was paid backwages from 16th January, 1976 viz., the date on which the Supreme Court rendered judgement in the "Sundermoney Case". By its circular No. PER. 401-3-3 dated 27th January 1984 the Respondent Bank decided to confirm all the reinstated workmen retrospectively w.e.f. 2-1-1981 with a notional period of probation of 6 months. Sri Ramakrishna Rao was called for interview on 14-4-1984. Thereafter he was called for a "Medical Examination" on 11-1-1985, viz. one year from the time of the circular regarding confirmation and 9 months after the interview. He was again subjected to a medical examination in April 1985. The Specialist to whom Sri Ramakrishna Rao was referred in April 1985 certified that the workman was fit and that his vision was satisfactory. Seven months later, on 15-11-1985, Ramakrishna Rao was subjected to another medical examination and the Respondent Bank purported to act of the opinion on that body and proposed to terminate the services of Sri Ramakrishna Rao. All the other workmen reinstated along with Sri Ramakrishna Rao were confirmed in service retrospectively as of 2-1-1981. The Respondent Bank discriminated against Ramakrishna Rao by treating him as "temporary" and denying him the benefits like admission to the Provident Fund, supply of uniforms, encashment of leave etc. Since there was no follow up action on the part of the Respondent Bank, the Union wrote on 3-8-1986 to the Chief Regional Manager of the Bank, Tirupathi, requesting him to cause immediate action to confirm Sri Ramakrishna Rao with retrospective effect and to extend to him all the attendant and consequential benefits. The Union therefore submits that the action of Respondent Bank to terminate the services of Ramakrishna Rao in terms of Section 25-F of the I. D. Act is clearly arbitrary and illegal and colourable. The workman Sri Ramakrishna Rao moved the High Court of Andhra Pradesh through a Writ Petition (W. P. No. 13790 of 1987) which was admitted by the Hon'ble High Court. The High Court also granted injunction restraining the Respondent Bank from giving effect to its notice dt. 24th August, 1987. The petitioner submits that after the High Court enjoined the Respondent, the order of reference dated 24th September, 1987 was received by the Petitioner on 28-9-1987. The Union submits the notice of proposed termination dated 9-10-1986 of which the notice dt. 24-8-1987 is only an extension, is clearly illegal and mala fide and is a clear act of unfair labour practice. Further, the proposed termination is also discriminatory and unjustified and amounts to victimisation, besides being colourable. The Union, therefore, submits that it is just and necessary that this Hon'ble Tribunal may be pleased to quash and set aside the notice dt. 9-10-1986 and its corollary notice dt. 24-8-1987 as illegal and inoperative and to direct the Bank to confirm Sri Ramakrishna Rao w.e.f. 2-1-1984 together with all attendant and consequential benefits and to pass such other or direction as the Hon'ble Tribunal may deem fit in the circumstances of the case.

3. The brief facts of the counter filed by the Respondent Bank is read as follows : It is true that Sri M. Ramakrishna Rao, initially joined as temporary godown watchman at Eluru

Branch on 1-1-1970. It is true that he has worked for 240 days. It may be noticed that as on that date, there was no judgement stating that if an employee works for 240 days, he is entitled for reinstatement. Sundermoney's case judgement came only in the year 1976. The Respondent Bank issued a circular on 27-1-1984 and decided to give benefit of reinstatement to all the extemporary employees and to absorb them in Bank's service subject to their suitability vis-a-vis the eligibility criteria including satisfying medical standards as per the guidelines which are in force in the Bank all over the country. It may be noticed that for the ex-temporary employees whom the Bank intends to absorb and even for the employees who are in normal course recruited, the same rule is provided so far as the medical fitness is concerned. It is respectfully submitted that the workman in dispute is having progressive opthalmic disease. As such, he could not be considered fit for the Messenger's post. So, the management has not regularised the services of the Petitioner workman and proposed to terminate him according to the guidelines of the Bank. This petitioner got examined himself and submitted a Certificate stating that he was medically fit. Inview of the contradictory opinions given by two different Doctors, the Medical Board was constituted, to afford a fair opportunity to the extemporary workmen, and the workman was asked to undergo the medical examination at the local head office on 15-11-1985. Sri M. Ramakrishna Rao has undergone the medical examination and the Medical Board found him unfit for the post of Messenger. The Medical Board report revealed his visual acuity of 6/24 in both eyes partially night blindness and primary R. P. is present in both eyes. The Medical Certificate issued by the Medical Board was examined by the Respondent Bank in the light of the medical guidelines and found that this employee is not suitable. After receipt of the Medical Board's report the Management has proposed to terminate the services of the Petitioner and the Union has raised a dispute. It is true that this Petitioner Union made representation to the Chief Regional Manager also. Even the Chief Regional Manager has perused the petitioner's case and found that it is contrary to the laid down procedure as a clear certificate was given by the Medical Board stating that he is unfit for the Bank job. It may be noticed that this reference is with regard to the "serving of notice of termination dt. 9-10-1986 on Sri M. Ramakrishna Rao, Messenger informing that his services will stand terminated w.e.f. 30-11-1986. 30-11-1986 has expired and no action has been taken by the Management on the said proposed termination order and the only action which was taken by the Management is on 24th August 1987. The workman is suffering from an incurable optic disease and as such he cannot carry on the job of a messenger. It is respectfully submitted that the reference itself is infructuous on this ground and therefore this Hon'ble Tribunal may be pleased to dismiss the claim petition.

4. The point for adjudication is whether the action on the part of the Management in serving notice of termination dt. 9-10-1986 on M. Ramakrishna Rao Messenger informing that his service will stand terminated w.e.f. 30-11-1986 is fair and justifiable ?

5. W.W.1 was examined on the behalf of the petitioner and Exs. W1 to W4 were marked. On the other side M.W1 and M.W2 were examined on behalf of the Respondent marked Exs. M1 to M14.

6. W.W1 is M. Ramakrishna Rao, the concerned workman himself. In brief he deposed that he joined the service in the Respondent Bank on 1-1-1970 as Godown Watchman. He was terminated from the service after 9 months. The Union took up his cause. He has reinstated on 10-8-1983 as per the order dt. 29-7-1983. The said order is Ex W1. He was paid his back wages for the period from 1976 to 1983 in the month of February 1984. He was called for interview in the month of April 1984 for permanent absorption in the service. He was called for medical test in January 1985. The management of the Respondent did not inform him the result of the medical test. Again he was sent for medical examination in April, 1985 and nothing is informed to him about the results of that medical test also. Again he was sent for medical test again in the month of November, 1985 to the local head office, Hyderabad and the results of that test was also not informed to him by the Respondent Bank. In October 1986 the Respondent terminated his services by the order dt. 9-10-1986. His services were terminated under Ex. W2 on medical grounds that his eye sight was defective. In the Writ Petition No. 13790 of 1987 filed by the Union, stay was

granted in his favour against the Respondent from terminating him from service. He prays that the action of the management of the Respondent Bank in serving the notice of termination dt. 9-10-1986 on his that his services will stand terminated w.e.f. 30-11-1986 may be declared as unfair and unjustifiable and to confirm his services, from the date of Ex. W4 the management did not issue any notice about his medical fitness or about his deficiency in discharging his duties.

7. M.W1 is M. Rama Murthy. In brief he deposed that he knows the facts of this case. He knows W.W1 was appointed as Godown Watchman on 1-1-1970 on temporary basis. He was terminated from services on 1-10-1970. Again he was temporarily appointed as Messenger on 10-8-1983, along with some other temporary employees that were removed previously, in view of judgement in Sundermani's case. After he joined the post, W.W1 was sent for medical examination to the Specialist Orthology by name Sri K. Venugopala Chary at Tirupathi. The Doctor gave a report stating that W.W1 was suffering primary R. P. that he is on treatment and that he may be improved. W.W1 got himself examined by another Doctor by name Sri Y. Venkataramana a special Ophthalmologist and produced certificate dt. 9-4-1985 and the photostat copy of the said certificate is Ex. M3. Later W.W1 was referred to a Medical Board constituted at the request of the respondent at Hyderabad and he was examined by the Medical Board and the Medical Board has given its opinion dt. 15-11-1985 and the photostat copy of the said medical board opinion is Ex. M4. It is stated in Ex. M5 that W.W1 cannot be continued.

8. The contention of the Petitioner that Sri M. Ramakrishna Rao joined the Eluru Branch of the Respondent Bank as Godown Watchman on 1-1-1970, the Bank illegally and unjustifiably terminated his service against he was reinstated into service and posted as Messenger at Tirupathi Branch on 10th August, 1983. It is also contended that he was paid back wages from 16th January 1976 viz. the date on which the Supreme Court rendered judgement in the Sundermoney case. Later he was called for interview on 14-4-1984 and thereafter he was called for a "Medical Examination" on 11-1-1985, again on April 1985 and again on 15-11-1985 and finally the Respondent Bank decided to terminate his service on the ground that he was medically unfit. Finally the concerned workman approached various authorities for the relief.

9. On the other hand the contention of the Respondent Bank that the Bank issued a Circular on 27-1-1984 and decided to give benefits of reinstatement to all the extemporary employees and to absorb them in Bank's service subject to their suitability vis-a-vis the eligibility criteria including satisfying standards as per the guidelines which are in force in the Bank all over the country, for regular appointment, medical fitness is compulsory. If they are not medically fit they are not appointed. On this basis the workman in dispute is having progressive opthalmic disease, as such, he could not be considered fit for the Messenger's post, and the Management proposed to terminate him according to the guidelines of the Bank.

10. The Circular No. PER 401-3-3 dated 27-1-1984 the Respondent Bank decided to confirm all the reinstated workmen retrospectively w.e.f. 2-1-1981 with a notional period of probation of 6 months. The Petitioner workman was called for interview on 14-4-1984. The Respondent did not stated anything of the interview conducted on 14-4-1984. I am at a loss to understand, what interview was conducted, what was the outcome of the result of the interview. Taking for granted that the interview conducted on 14-4-1984 the petitioner-workman might have successfully gone through. The next step was the Medical Examination. As per the version of the Petitioner-workman the Medication Examination was conducted on 11-1-1985. The norm is even if a candidate who has successfully got through the Banking Recruitment Board's Examination and appointment order is given to him, he has to become medically fit. If they are not medically fit, they are not appointed. The other aspect of the recruitment is for the ex-temporary employees whom the Bank intends to absorb and even for the employees who are in normal course recruited, the same rule is provided so far as the medical fitness is concerned. No doubt the petitioner-workman appeared for Medical Examination on 11-1-1985. I am surprised to find that nothing is said about the medical examination conducted on 11-1-1985 by the Respondent whether

the petitioner-workman was fit for the post or not. Again Medical Examination was conducted in April, 1985. The version of the Petitioner-workman is that the Specialist to whom Ramakrishna Rao was referred in April, 1985 certified that the workman was fit and that his vision was satisfactory as can be seen from Ex. M10. Nothing adverse was written in Ex. M10. The Respondent-Bank has not whispered anything of Ex. M10 or the result of Medical Examination conducting during April, 1985. Again the Respondent Bank took a last resort to some how terminate the petitioner-workman conducted a Medical Examination on 15-11-1985. In this medical examination unfortunately the Petitioner-workman was having progressive opthalmic disease, finally he could not be considered fit for the Messenger's post. It is pertinent to note that when once an interview is conducted and when once Medical Examination is conducted, the appointment order is given to the candidate. There is no such rule that when once the Medical Examination is conducted and found not fit, then another Medical Examination is conducted after a gap of period and the conduct another Medical Examination and found unfit for the post. There is no such guidelines in force in the Banks all over the country that Medical Examination should be conducted from time to time until the candidates becomes un-successful. From the above facts, it clearly indicates that the Respondent Bank had discriminated against Ramakrishna Rao by treating him as "temporary" and denied him the benefits like admission to the Provident Fund, supply of Uniforms, Encashment of leave etc. I find all these acts as unfair labour practices and discrimination against the petitioner-workman and taken the extreme step of terminating the services of the petitioner-workman. It is also found that the petitioner-workman was discriminated in relation to other reinstated workmen. Thus I am of the clear view that the Respondent-Bank has resorted to unfair labour practice of keeping the petitioner-workman temporary without confirming him in service. This Tribunal is left with no other alternative except to reinstate Sri M. Ramakrishna Rao, Messenger into service w.e.f. 30-11-1986.

11. In the result, the action of the part of the Management of State Bank of India in relation to Region-III, Tirupathi in serving notice of termination dt. 9-10-1986 on Sri M. Ramakrishna Rao, Messenger informing that his services will stand termination with effect from 30-11-1986 is not fair and unjustified. Sri M. Ramakrishna is entitled to be reinstated into service with effect from 30-11-1986 with full back wages and all other attendant benefits.

Award passed accordingly.

Typed to my dictation, given under my hand and seal of this Tribunal, this the 27th day of September, 1973.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I.

Appendix of Evidence

Witnesses Examined on behalf of the Petitioner/Workman :

W.W1 M. Rama Krishna Rao

Witnesses Examined on behalf of the Respondent/Management :

M.W1 M. Ram Murthy

M.W2 T. Nagendra Prasad.

Documents marked for the Petitioner/Workman :

- Ex. W1 29-7-83.—Order dt. 29-7-83 issued by the Regional Manager, State Bank of India, Tirupathi with regard to temporary appointment of Sri M. Ramakrishna Rao as Messenger.
- Ex. W2 9-10-86.—Photostat copy of the Order issued by the Branch Manager, State Bank of India, Tirupathi with regard to terminate of Sri M. Ramakrishna Rao, Temporary Messenger w.e.f. 30-11-86.
- Ex. W3 5-2-86.—True Copy of the minutes of discussions held on 5-2-86 between the Management of S.B.I., Region-III, Tirupathi and their workmen by State Bank of Employees' Union, Vijaywada regarding alleged non-confirmation of service of Sri M. Ramakrishna Rao, Messenger, S.B.I., Tirupathi Branch.

AWARD

Ex. W4 24-8-87.—Photostat copy of the Order issued by the Branch Manager, S.B.I., Tirupathi with regard to termination of Sri M. Ramakrishna Rao, Temporary messenger w.e.f. 24-9-1987.

Documents marked for the Respondent/Management :

Ex. M1 28-6-91.—Personal statement of the candidate/Promotee to be filled in by the Candidate/Promotee before presenting the Form to the Medical Officer.

Ex. M2 10-1-85.—Report of the Medical Examiner.

Ex. M3 15-11-85.—Report of the Medical Examiner.

Ex. M4 15-11-85.—Opinion of the Medical Board.

Ex. M5 15-11-85.—Medical Examination by Special Board conducted on 15-11-85.

Ex. M6 9-10-86.—Letter of intimation of decision of Medical Board to the W.W1.

Ex. M7 7-3-85.—Office Note No. 264.

Ex. M8.—Original of Ex. M1.

Ex. M9.—Original of Ex. M2.

Ex. M10.—Original of Ex. M3.

Ex. M11.—Original of Ex. M4.

Ex. M12.—Original of Ex. M5.

Ex. M13.—Original of Ex. M6.

Ex. M14.—Original of Ex. M7.

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1993

का.प्रा. 2367—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन के संरक्षित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, मतभेद में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती, जो केन्द्रीय सरकार को 12-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[नं.प्रा.एल-12012/234/88-डी-3(ए)]

एम.एस.के. राव, डी.एस. अधिकारी

New Delhi, the 13th October, 1993

S.O. 2347.—Whereas by the notification of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 12-10-93.

[No. L-12012/234/88-D.III(A)]

S. S. K. RAO, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I.D. 23/89

A. S. Makkar Vs. State Bank of India
For the workman : Shri J. G. Verma
For the management : Shri Ashok Khullar

Central Govt. vide Gazette Notification No. L-12012/234/88-D.III(A) dated 10th February 1989 issued U/S 10(1) (d) of the I. D. Act 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

“Whether the action of the State Bank of India, Regional Office, Haryana and UT in ignoring Shri A. S. Makkar, Teller at Section 7 branch of SBI, Chandigarh from appearing in test in the year 1982, 1984 were legal and justified? If no, to what relief is the concerned workman entitled to and from what date?”

2. Case of the petitioner as set out in the statement of claim that he joined services of the bank in permanent capacity on 22-4-1974 and was transferred thereafter. The management decided to hold promotion test on 26-9-1982 and the petitioner though eligible was illegally denied his right as his name was not included in the list of the candidates called to write the test. He made representation on 21-2-1983 in which the management admitted their lapses but tried to shift their responsibility on him. He made further representations but was conveyed on 14-12-1983 not to agitate the issue or to face the consequences. He, therefore kept silent. It is further alleged that again in the year 1984 a test was held. Although his name was included in the list but he was not relieved by the manager to appear in the test and alleges mala fide intention at the hands of the respdt. management. It is further alleged that thereafter also he was not allowed to appear in the test which is against the norms of equity, justice and in violation of bank's own instructions. He has thus sought promotion w.e.f. 1982 when his juniors were promoted alongwith difference of wages alongwith interest and penalty.

3. The management has opposed the claim of the petitioner. In written statement they admitted to the extent that departmental promotion test was held on 26-9-1982. However plea of the management is that the petitioner's eligibility for promotion was considered and his name was included in the list of eligible candidates for appearance in the said test. It was displayed at the notice board. The petitioner, however, choose to ignore and proceeded on leave to avail the L.F.C. without leaving even his address with his controlling authority. Since it was not possible to communicate him, therefore, bank had not denied any of the opportunity to him for taking a chance in the test. Thereafter in the promotion test held on 7-10-1984 petitioner's name was included in the list and circulated in the branch in reference to the concerned persons in the casual manner. Incidentally in the list the petitioner's name was mentioned as Amrik Singh instead of A. S. Makkar. The petitioner instead of apprising the concerned authority at the appropriate time choose to remain silent. Therefore, his claim is after thought. It has also been pointed out that in the said branch there is only one person by the name of Amrik Singh and that is the petitioner. The petitioner never represented for his relieving in order to appear in the test thus deliberately avoiding to sit in the promotional test and sought the dismissal of the reference.

4. Replication was also filed reasserting the claim made in the statement of claim.

5. The petitioner in support of his case produced himself as WW1 and filed his affidavit Ex. W1. He also relied on documents Ex. W2 to W9. The respdt. management produced MW1 S. K. Sharma Branch Manager. He filed his affidavit Ex. M1. He also relied on documents Ex. M2 to M4.

6. I have heard both the parties, gone through the evidence and record.

7. Grievance of the petitioner in the present case is that he was not allowed to appear in the promotional test held on 26-9-1982 and as well on 7-10-84 and thus has sought promotion treating as having cleared the test. The contention raised by the petitioner is meritless. First promotional test had admittedly taken place on 26-9-1982. The relevant facts which can be gathered from Ex. W3 the reply of the management in response to representation of the petitioner and the subsequent representation dated 9-5-1983 Ex. W4 is that the test had taken place on 26-9-1982 whereas the petitioner had proceeded on leave from 16-9-1982 to 1-10-1982. The petitioner got the leave sanctioned a month prior to 16-9-1982 obviously his name could not have reflected in the list for promotional test for JMGS-1 which was only circulated on 16-8-1982. Even if there is inadvertence on behalf of the management, the petitioner could represent immediately after circulation of the list to the effect that his name does not appear and could sought the cancellation of his leave for the purpose of appearing in the test but he remained silent on this issue and proceeded on leave on 16-9-1982 avoiding the date of test i.e. 26-9-1982. He has also not proved by way of any documentary evidence that he had left the address of place where he proceeded on leave which is required under the rules. Otherwise also even if he had left his address of a place where he proceeded on LFC it was not incumbent upon the management to intimate him the date of test having petitioner not expressed his desire to appear in the test in response to the circular dated 16-8-1982 till date he proceeded on LFC on 16-9-1982 obviously not interested to appear in the test. The petitioner started making representations after the test although it was expected from him to make the said representations prior to the test as there was sufficient time for about one month to get his name included in the

list of eligible candidates but he did not react and kept silent.

8. Similarly for the promotional test held on 7-10-84 the petitioner has shown his grievance that although his name is A. S. Makkar but the name appeared in the list is Amrik Singh and thus he was not aware of the test and was also not relieved by the branch manager to appear in the test. This plea is again meritless. Ex. M3 is the service sheet of the petitioner where in column of name is written 'Amrik Singh'. No matter the petitioner claims himself to be A. S. Makkar but the list of the eligible candidates obviously would contain the name of the person as per from service sheet. The petitioner also himself admits in cross-examination that his name is Amrik Singh and in the concerned branch where he was working there is no other employee by the name of Amrik Singh. In that situation it is not open for the petitioner to say that from the name of Amrik Singh in the list he could not gather that the same relates to him. The petitioner has not shown any rules that mere inclusion the name in the list for promotional test ipso facto amounts to issuance of a relieving order by the concerned branch manager to a employee enabling him to appear in the test. As evident an employee is required to express his willingness to the concerned branch manager to appear in the test only then his relieving order could be passed by the branch manager. It is no where in the present case to the effect that the petitioner had approached the authority or shown any willingness to appear in the test and as such no relieving order could be passed and for no fault of the management.

9. From the scrutiny of the evidence as discussed above it seems that the petitioner wants promotion without having passed the promotional test although it is evident that the petitioner himself has deliberately avoided to appear in the test. He can not be allowed to cash his own wrongs.

10. Hence nothing survive in the proceedings initiated by the petitioner and he is not entitled to any relief what soever. In a way reference is answered accordingly.

Chandigarh

Dt. 30-9-1993.

ARVIND KUMAR, Presiding Officer

